सुबह सवेरे

A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 30 जून, 2025

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 22, अंक 291, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

पहली बात

'एस्ट्रोनॉट' का खूबसूरत 'अर्थ-हाउस' वस्तुतः 'हॉट-स्पॉट' है...

उमेश त्रिवेदी
प्रधान संपादक

जमीन से 4 सौ किलोमीटर से ऊपर आसमान की निशब्द नीरव बुलंदियों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ संवाद में उभरे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के रूह अफजा अल्फाज जहन में उस 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा' नगमें की तरन्नुम गुनगुनाने लगते हैं, जिसे पहले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 41 साल पहले चांद की सतह से उकेरा था। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सेंटर में वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं। राकेश शर्मा जब एस्ट्रोनॉट बने थे, तब यह सेंटर स्थापित नहीं हुआ था। 1961 से अबतक दुनिया के 600 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष कर यात्रा कर चुके हैं। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को रूसी सोयुज टी-11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बातचीत में राकेश शर्मा ने कहा था कि 'सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा'।

41 साल बाद आज शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 18 मिनट 25 सेकंड तक अपने अनुभव साझा किए। संवाद के दरम्यान शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री से कहा कि- 'जब मैंने पहली बार अंतरिक्ष से भारत को देखा तो वह नक्शे से कहीं ज्यादा विशाल और भव्य नजर आया।' उन्होने कहा कि 'यहां अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर एकता का असली एहसास होता है। कोई सीमाएं नही दिखती हैं। कोई लकीरें नहीं होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी पृथ्वी हमारा घर है और हम सभी इसके नागरिक हैं।'

प्रधानमंत्री मोदी से शुभांशु शुक्ला की बातचीत लंबी थी, लेकिन हमारे देश, हमारी जमीन, हमारी पृथ्वी के बारे में शुभांशु ने जो कहा, वह गौरतलब है। भारत के लिए शुभांशु का कथन गुदगुदाता है, लेकिन पृथ्वी के बारे में उनका नजरिया थरथराता है। एक एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मनुष्यता की एकात्मता का यह परिदृश्य देख सकता है, लेकिन भू-राजनीति के बीहड़ों में तो खूनी ताकतें ही राज करती हैं। पृथ्वी के भूगोल में सभ्यताओं के इतिहास का खलल उन लकीरों को स्याह बना रहा है, जो लकीरें शुभांशु शुक्ला जैसे एस्ट्रानॉट-वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से नजर नहीं आती हैं। शुभांशु जैसे एस्ट्रोनॉट भले ही अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से समूचे मानव समाज के बीच लकीरों के अस्तित्व को नकारें, लेकिन भू-राजनैतिक अवधारणाएं सीमा-हीनता को कभी भी कबूल नहीं करती हैं। विज्ञान भौगोलिक सीमाओं से परे इंसान और इंसानियत को सहेजने और संवारने के लिए सक्रिय है, लेकिन सियासी फितरत उसे गर्त की ओर ढकेल रही है। एस्ट्रोनॉट के लिए भले यह दुनिया याने 'अर्थ', एक 'हाउस' हो, लेकिन उन वर्ल्ड-लीडर के लिए तो यह दुनिया लूट का खजाना है।

दुनिया में ऐसे कई भू-राजनीतिक हॉट-स्पॉट हैं, जो विचारधारा, संसाधन और क्षेत्रीय हितों के नाम पर ज्वालामुखी की तरह विनाश के लावा उगल रहे हैं। रूस-यूक्रेन, इजराइल-ईरान-फिलिस्तीन और भारत-पाकिस्तान के बीच ताजा संघर्षों की तथा-कथा के बीच चीन-ताइवान आमने-सामने खड़े हैं। दक्षिण चीन सागर, मध्य-पूर्व और पूर्वी यूरोप बारूद के ढेर पर बैठे हैं। शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को बताया कि वो चौबीस घंटों में 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। यह उनकी खुशनसीबी है कि वो चौबीस घंटों में सोलह बार सूर्योदय और सूर्यास्त देख रहे हैं। याने हर डेढ़ घंटे में उनके सामने सूर्य उगता और अस्त होता है।

वो नियति के अद्भुत चमत्कार के रूबरू हैं, लेकिन ये चमत्कार दुनिया की भू-राजनैतिक परिस्थितियों के सामने असहाय हैं। आकाश-गंगा की ये वैज्ञानिक-सत्य कथाएँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू या ईरान के सर्वोच्च नेता इस्लामी गणराज्य के प्रमुख अयातुल्लाह अली खामेनेई के विस्फोटक भू-राजनैतिक युद्धों की संहारक-सत्य कथाओं की विनाश-लीलाओं के सामने कराहती और सिसकती महसूस हो रही हैं। पृथ्वी के भीतर छिपे नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने को होड़ में इन राष्ट्राध्यक्षों ने दुनिया को बारूद के जखीरों में बांट दिया है। प्राकृतिक संसाधनों की हवस में ये नेता मनुष्यता को युद्ध में झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन लड़ाइयों में होने वाला नुकसान और तबाही हैरतअंगेज है।

आकलन करें तो ईरान और इजराइल के बीच बारह दिनो के ताजा युद्ध में दोनो देशों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस युद्ध में इस्तेमाल राकेटों और मिसाइलों के हमलों ने जहां दोनो देशों के नागरिक ठिकानो पर भारी तबाही मचाई है, वहीं आर्थिक रूप से दोनो राष्ट्र घुटने के बल खड़े नजर आ रहे हैं। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के विश्लेषण में कहा गया है कि इस लड़ाई में ईरान को करीब 200 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि इजराइल को 12 अरब डॉलर की तबाही झेलनी पड़ी है।

ईरान की तबाही के आंकड़ों का मूल्यांकन भी इससे कम नहीं है। इस लड़ाई में लगभग 800 लोगों की मौत हुई है। इनमें 263 रिवोल्युशनरी गार्ड के कई शीर्ष कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी शरीक हैं। अमरीकी सैन्य हमलों में नतांज और फोर्डो परमाणु केन्द्रों पर महती नुकसान के अलावा तेल-उत्पादन के क्षेत्र में ढाई अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तेल के इन्फ्रास्ट्रक्चर की तबाही की लागत चार अरब डॉलर आंकी गई है। तेल उत्पादन के निर्यात और उत्पादन में हुए नुकसान ने जीडीपी पर 9.6 अरब डॉलर का नकारात्मक प्रभाव डाला है। जबकि ईरानी-मिसाइलों ने इजराइल में 4.2 अरब डॉलर का इन्फ्रास्ट्रक्चर तबाह किया है। 2 अरब डॉलर का औद्योगिक उत्पादन का नुकसान इसके अलावा है।

अब हम फरवरी 2022 से जारी रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध की ओर मुखातिब हों तो विश्व बैंक के अनुसार युक्रेन में प्रत्यक्ष तबाही का आंकड़ा 152 बिलियन डॉलर है। यहां भौतिक तबाही के मंजर हैरतअंगेज और दिल हिला देते हैं। कह सकते हैं कि यूक्रेन विनाश की कगार पर खड़ा है। रूस भी युद्ध के दुष्प्रभावों से अछूता नहीं है। रूस ने नवम्बर 2022 में आधिकारिक तौर पर कबूल किया था कि युद्ध ने उसकी इकॉनमी को मंदी में ढकेल दिया है। राष्ट्रीय जीडीपी संकट के दौर से गुजर रही है। अनुमानों मे कहा गया है कि युक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को प्रति दिन 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के बीच नुकसान हो रहा है। 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तीन साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध में अभी तक दोनो पक्षों के दस लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मृतकों मे अधिकांशतः दोनो पक्ष के सैनिक हैं। जबकि यूक्रेन का दावा है कि अभी तक लड़ाई में रूस अपने दस लाख सैनिकों को खो चुका है। यह सिलसिला रूकने वाला नहीं है, क्योंकि संसाधनों की हवस ने अमेरिका, रूस अथवा चीन जैसे ताकतवर देशों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है।

subhahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

मौन चीखता आज भी, सन्नाटे में शोर।
आई फिर हरसूद की, यादें हूक हिलोर।।

सावन भादों नयन थे, टुकुर टुकुर घर द्वार।
कृष्ण निहारें द्वारका, जैसे अन्तिम बार।।

लालच बढ़ा विकास का, किया प्रकृति से युद्ध।
नष्ट हुए वन, खेत सब, जल भी रहा न शुद्ध।

ह्रदय ह्रदय ज्वालामुखी, कौन बँधाये धीर।
जन, मन, पर्वत, मृत्तिका, पीर नर्मदा नीर।।

था निमाड़ के मुकुट में, हीरे सा हरसूद।
शोभित ज्यों नवरत्न सा, था बहुग्राम वजूद।।

हुआ नहीं हरसूद ही, केवल एक शिकार।
दो सौ पचपन गाँव ने, झेला वज्र प्रहार।।

जितनी चढ़ी सलाइनें, उतनी टूटी साँस।
धीरे धीरे धँस गयी, यह विकास की फांस।।

समय किसी का कब हुआ, मित्र, शत्रु या दास।
राजतिलक के थाल में, छिप रहता वनवास।।

पेट काट जो घर बना, तिनका तिनका जोड़।
किन्तु कलेजा मुँह लिए, दिया उसे ही तोड़।।

अपनों के हित हेतु ज्यों, रण स्वीकारें वीर।
स्वजन सहित हरसूद ने, अपना तजा शरीर।।

लुप्त हुए सब चैतुए, बिखर गए घर द्वार।
नित जन गण मन तौलता, कागज का अम्बार।।

इसका कौन हिसाब दे, मूल घटा ना सूद।
आखिर किस अपराध में, डूब गया हरसूद।।

डबिंग फ़िल्म सा बन रहा, आज नया हरसूद।
जो सौंधा हरसूद था, उसका कहाँ वजूद।।

याद रखेंगी पीढियां, चुका न पाएं सूद।
कह पाएं केवल यही, धन्य धन्य हरसूद।।

कल भी था, अब भी यहीं, यादों में हरसूद।
अब भी अमर दधीचि सा, जिन्दा है हरसूद।।

– अशोक चन्द्र दुबे 'अशोक'

बाढ़-बारिश का कहर संकट में गांव और शहर

झारखंड में बाल-बाल बचे बाढ़ में फंसे 162 बच्चे

यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 2 मजदूरों की गई जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। झारखंड के जमशेदपुर में लव कुश आवासीय स्कूल में फंसे 162 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बारिश के बाद स्कूल में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों को बचाया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। उत्तराखंड में शनिवार से भारी बारिश जारी है। यहां चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। यात्रियों को हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर में ही रोकने के आदेश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर लापता हैं। वहीं, बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। अलकनंदा और सरस्वती भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आमतौर पर यह 8 जुलाई तक होता है, लेकिन इस बार मानसून 9 दिन पहले ही पूरे देश में फैल गया। देशभर में रविवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पाकिस्तान ने भारत पर लगाया सुसाइड बम अटैक का आरोप

- इसमें 13 सैनिक मारे गए थे

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले में सैन्य काफिले पर सुसाइड बम अटैक का आरोप भारत पर लगाया है। इसमें 13 सैनिकों की मौत हुई थी। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों का खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान पर हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है। हम इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक है।

जगन्नाथ रथयात्रा के बाद भगदड़, 3 लोगों की मौत

50 लोग हुए घायल, मुख्यमंत्री माझी ने मांगी माफी

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथयात्रा के बाद रविवार तड़के करीब 4 बजे भगदड़ मच गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 घायल हो गए। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। हादसा जगन्नाथ मंदिर से करीब 3 किमी दूर गुंडिचा मंदिर के सामने हुआ। यहां भगवान जगन्नाथ के नंदीघोष रथ के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुटी थी, इसी दौरान भगदड़ मची। सीएम मोहन चरण माझी ने घटना पर माफी मांगी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी भक्तों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगते हैं। यह लापरवाही माफ करने लायक नहीं है।' इसके बाद राज्य सरकार ने पुरी के कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया। चंचल राणा को नया कलेक्टर और पिनाक मिश्रा को नया एसपी बनाया गया है। साथ ही डीएसपी और कमांडेंट को निलंबित कर दिया गया है। पुरी की रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के सामने 9 दिन के लिए खड़ा कर दिया जाता है। यहां बलभद्र और सुभद्रा के रथ पहले पहुंच चुके थे। जगन्नाथ रथ बाद में पहुंचा, जिससे लोगों में उसके दर्शन करने की होड़ लग गई। इसी दौरान भगदड़ मची, जिसमें कई लोग कुचल गए।

आने वाले समय में और सशक्त होगा भारत

पीएम मोदी ने कहा-जनभागीदारी से देश और आगे बढ़ रहा है

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 123वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने योग दिवस के बारे में बात की। उन्होंने

- मन की बात में बोले-इमरजेंसी में लोगों को प्रताड़ित किया गया

कहा- 21 जून को देश-दुनिया के करोड़ों लोगों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लिया। योग की भव्यता बढ़ती जा रही, लोग दैनिक जीवन में इसे अपना रहे। पीएम ने कहा- इस बार हमने योग दिवस की आकर्षक तस्वीरें देखीं। विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। हमारे नौसेना ने जहाजों पर और जम्मू में लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर योग किया। वडनगर में 2100 लोगों ने एक साथ भुजंगासन करके रिकॉर्ड बना दिया। पीएम ने आगे कहा- इमरजेंसी के दौर में लोगों को प्रताड़ित किया गया। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। उन पर ऐसे ही अमानवीय अत्याचार किए गए। आखिर में जनता की जीत हुई और आपातकाल हटा लिया गया। जनता की जीत हुई और आपातकाल लगाने वालों की हार हुई। इंटरनेशनल लेबल ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। इसमें सामने आया है कि देश के 95 करोड़ लोग किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इन सफलताओं ने एक विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में भारत और सशक्त होगा। साथियों, जनभागीदारी से देश और आगे बढ़ रहा है। धार्मिक यात्राएं सेवा के अवसर का महाअनुष्ठान होती है। जितने लोग यात्रा में जाते हैं उससे ज्यादा लोग उनकी सेवा में जुट जाते हैं। लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई है।

शिवराज सिंह क्षेत्र के आदिवासियों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे

अभयारण्य में ग्रामीणों के घर तोड़े गए थे, शिवराज की शिकायत पर सीहोर डीएफओ हटाए गए

भोपाल (नप्र)। रविवार को शिवराज, क्षेत्र के आदिवासियों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे जहां उन्होंने सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर मंत्री शाह खिवनी पहुंचे।

देवास जिले के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के खिवनी में 23 जून को वन विभाग ने आदिवासियों के 50 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया था। घटना के बाद सीहोर में पीड़ित आदिवासी परिवारों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी।

रविवार को शिवराज, क्षेत्र के पीड़ितों को साथ लेकर सीएम हाउस पहुंचे। सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात के दौरान खातेगांव और इछावर क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों के साथ बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद थे।

वहीं, सीएम के निर्देश पर मंत्री विजय शाह कीचड़ भरे रास्ते पर तीन-चार किलोमीटर पैदल चलते हुए खिवनी गांव पहुंचे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद वे ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर अधिकारियों के साथ गांव से निकले। बता दें, शाह कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देकर विवाद में फंसे हैं।

सीएम ने सीहोर डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटाया- शिवराज से हुई मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीहोर के डीएफओ मगन सिंह डाबर को हटा दिया है। डाबर को भोपाल भेजा गया है। अर्चना पटेल को सीहोर का नया डीएफओ बनाया है। खिवनी अभयारण्य सीहोर वन मंडल क्षेत्र में आता है। ऐसे में पहली कार्रवाई डीएफओ पर ही की गई है। 23 जून को आदिवासियों के 50 से अधिक कच्चे मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाया गया था। सीएम ने दिया था मदद का आश्वासन।

बारिश के सीजन में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें- शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम हाउस में आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सीएम डॉ मोहन यादव ने एक्स पर लिखा- हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के साथ है। आज भोपाल निवास पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मौजूदगी में खिवनी अभयारण्य के लिए वन विभाग की कार्रवाई से प्रभावित जनजातीय समुदाय के नागरिकों से भेंट की।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 30 जून 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

दिल्ली में मोदी की हर गारंटी झूठी और नकली निकली

● अरविंद केजरीवाल बोले, पीएम पर लगा दिया बड़ा आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में झुग्गियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- मोदी की गारंटी झूठी, फर्जी और नकली है। आगे कभी जिंदगी में मोदी की गारंटी पर भरोसा मत करना। केजरीवाल ने कहा- चुनाव के समय मोदी जी ने आपको गारंटी दी थी- 'जहां झुग्गी-वहां मकान।' उनका मतलब

था- 'जहां झुग्गी-वहां मैदान।' वो ये कहना चाहते थे मुझे वोट दे दो, मैं सारी झुग्गियां तोड़ दूंगा और मैदान बना दूंगा। भाजपा का प्लान दिल्ली की सभी झुग्गियां तोड़ने का है। इनकी गंदी नजर आपके घरों पर टिकी हुई है। दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा झुग्गीवाले हैं, यह सभी इकट्ठे होकर सड़कों पर आकर आंदोलन करेंगे। मैं भाजपा को चेतावनी देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, झुग्गियां तोड़ना बंद करो। अगर झुग्गियां तोड़ना बंद नहीं किया तो तुम्हारा सिंहासन डोलने में वक्त नहीं लगेगा। चुनाव से पहले मैंने दिल्ली के गरीबों और झुग्गीवालों के लिए वीडियो जारी करके कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आ गई तो यह एक साल में ही झुग्गियां तोड़ देंगे।

ठाकरे बंधुओं को मिला शरद पवार का साथ

● महाराष्ट्र में भाषा विरोध-प्रदर्शन में होंगे शामिल

मुंबई (एजेंसी)। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) ने ठाकरे बंधुओं की ओर से 5 जुलाई को बुलाए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने की घोषणा की है। एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष जयंत पाटिल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस मार्च में बड़ी संख्या में भाग लेने की भी अपील की। पाटिल की ओर से शुक्रवार शाम को जारी बयान में कहा गया, एनईपी 2020 की त्रि-भाषी नीति के तहत हिंदी के थोपे जाने के विरोध में

मुंबई में मराठी भाषी नागरिकों की विशाल रैली होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) ने इस मार्च को अपना पूरा समर्थन दिया है। एससीपी (एसपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी विरोधी नहीं हैं, लेकिन पहली कक्षा से चौथी तक के विद्यार्थियों पर यह भाषा थोपना उचित नहीं है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पवार ने कहा कि देश की 55 प्रतिशत आबादी हिंदी बोलती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पवार की यह टिप्पणी महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच आई है, जो पिछले सप्ताह राज्य सरकार की ओर से संशोधित आदेश जारी करने के बाद शुरू हुआ था। इसमें कहा गया कि हिंदी को आम तौर पर कक्षा एक से पांच तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा।

जल गंगा संवर्धन अभियान

पीएम मोदी जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह को वर्चुअली करेंगे संबोधित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 1518 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि-पूजन, खंडवा में 30 जून को अभियान का होगा भव्य समापन, वाटर-शेड सम्मेलन भी होगा

भोपाल (नप्र)। पानी की हर बूंद को सहेजने के उद्देश्य से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन और वॉटरशेड सम्मेलन सोमवार 30 जून को खंडवा में होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअल शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 1518 करोड़ रुपये से अधिक के जल संरक्षण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर मध्यप्रदेश में 3 माह के लिए 'जल गंगा संवर्धन अभियान' चलाया गया। इस दौरान जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन पर लगातार कार्य किया गया। सोमवार को अभियान के समापन कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 578.08 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए 57 हजार 207 जल संरक्षण कार्य, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वॉटरशेड विकास के अंतर्गत 63.46 करोड़ रुपये की लागत से 888 जल

संरक्षण के कार्य, वॉटरशेड परियोजनाओं के कार्यों के प्रबंधन और अनुश्रवण के लिए वॉटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लोकार्पण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जल संसाधन विभाग की 4 सिंचाई परियोजनाओं क्रमशः भाम राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना, बिहार सारोला बैराज, लाजैरा बैराज, हापला दीपला बैराज लघु सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं की लागत करीब 312.77 करोड़ रुपये है, जिससे 8557 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे 21 ग्रामों के 7260 किसान लाभांवित होंगे। नर्मदा घाटी विकास विभाग की जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना प्रशासकीय स्वीकृति रुपए 563.72 करोड़ का लोकार्पण भी किया जाएगा। योजना से खण्डवा जिले के 52 ग्रामों के 21,666 किसानों की करीब 26 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान में अमृत 2.0 योजना अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार की गई 74 जल संग्रहण संरचनाओं का लोकार्पण किया जाएगा।

अहमदाबाद विमान हादसे में अब साजिश समेत हर एंगल से होगी जांच

नई दिल्ली (एजेंसी)। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया विमान हादसे की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है, जिसमें साजिश (सबोटाज) की संभावना को भी खंगाला जा रहा है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दी है। उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच कर

● केंद्रीय मंत्री बोले-ब्लैक बॉक्स भारत के पास, इन्वेस्टीगेशन के लिए विदेश नहीं भेजेंगे

रहा है। ब्लैक बॉक्स भारत में (एएआईबी के पास) है, उसे बाहर नहीं भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री मोहोल पुणे में एक चैनल के कार्यक्रम एमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। एएआईबी इसकी हर एंगल से जांच कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और कई एजेंसियां मिलकर जांच में जुटी हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट एआई 171 टेकऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्र जिंदा बचा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है कि यह इंजन फेलियर, फ्यूल सप्लाई की समस्या या कोई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हुआ। ब्लैक बॉक्स में मौजूद सीवीआर और एफडीआर की जांच की जा रही है। 3 महीने में रिपोर्ट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि डीजीसीए (नागर विमानन महा निदेशालय) के आदेश पर एअर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों की जांच कर ली गई है और सब कुछ सुरक्षित पाया गया है। ये हादसा एक अपवाद था, अब लोग बिना डर के यात्रा कर सकते हैं। एअर इंडिया के ड्रीमलाइनर प्लेन हादसे की जांच में संयुक्त राष्ट्र शामिल होगा। संयुक्त राष्ट्र की विमानन संस्था आईसीएओ (इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन) के एक विशेषज्ञ को ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने की इजाजत भारत सरकार ने दे दी है। आईसीएओ ने जांच में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। भारत ने पारदर्शिता के साथ जांच करने के इरादे से संयुक्त राष्ट्र को इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। हादसे की जांच 13 जून से ही एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की टीम कर रही है। इसमें विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अफसर और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

'मन की बात' कार्यक्रम में बालाघाट की बहन का शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 1 और 2 जुलाई को संपन्न होगी : विष्णुदत्त शर्मा

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को मध्य विधानसभा के अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक 159 स्थित कम्युनिटी हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत कम्युनिटी हॉल परिसर में पौधारोपण किया। मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बालाघाट जिले के कटंगी की बहन सुमा उइके के आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों की विस्तार से चर्चा की है, जो प्रदेश की सभी बहनों के लिए प्रेरणादायक है, साथ ही हम सभी के लिए गर्व की बात है।

सार्थक हो रहे प्रधानमंत्री जी के प्रयास - भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हमने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है। प्रधानमंत्री के प्रयासों के चलते अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज सारी दुनिया में मनाया जाता है और इतना लोकप्रिय हो चुका है, जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। योग आज देश और दुनिया में हर वर्ग के लोगों के लिए निरोग रहने का

माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यक्रम में बताया कि किस तरह भारत का जल-जीवन मिशन दूषित पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर रोक लगाने में कामयाब हो रहा है। अब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि बीमारी मुक्त भारत प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 25 जून को हमने संविधान हत्या दिवस मनाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचल दिया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में उस समय विपक्ष के नेता स्वर्गीय मोरार जी देसाई, बाबू जगजीवन राम, श्रद्धेय अटल जी की प्रतिक्रियाओं को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। आपातकाल के बारे में इन नेताओं का एक्चुअल वर्जन उन्हीं की आवाज मे सुनना सभी के लिए एक रोमांचक अनुभव रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि हम सभी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बालाघाट जिले की कटंगी की बहन सुमा उइके की चर्चा कर बताया कि किस तरह यह बहन स्व-सहायता समूह के माध्यम से मशरूम उत्पादन और पशुपालन के काम करके आर्थिक रूप से सशक्त बन रही है।

छात्रा से जोर जबर्दस्ती करते दिख रहे गैंगरेप के आरोपी

कोलकाता मामले में सीसीटीवी फुटेज से हो गई पुष्टि

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हुई है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3.30 बजे से रात 10.50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज हैं। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबर्दस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं, जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था, शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अब तक कुल चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा मामले में शुक्रवार को गठित स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम में आज मेंबर्स की संख्या पांच से बढ़ाकर नौ कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रदीप कुमार घोषाल इसे लीड कर रहे हैं। घटना 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई थी। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा (31) है। घटना में जैब अहमद

(19) और प्रमित मुखर्जी (20) भी शामिल हैं। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के छात्र हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़ित से रेप की पुष्टि हुई पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में शनिवार को रेप की पुष्टि हुई।

राजा हत्या कांड

शिलोम के ससुराल में मिला सोनम का लैपटॉप !

● किचन से मिले बैग से खुलेंगे हत्याकांड के कई राज

भोपाल (एजेंसी)। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस को एक और नया सबूत मिला है। शिलांग एसआईटी की टीम प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को उसके ससुराल रतलाम लेकर पहुंची। वहां पर एसआईटी ने तलाशी ली तो किचन से एक बैग मिला है। एसआईटी की टीम ने बैग में रखे सामान का पंचनामा बनाया और अपने कब्जे में ले लिया। सूत्रों के अनुसार इस बैग में सोनम के लैपटॉप का होना बताया जा रहा है। दरअसल, शिलांग पुलिस शिलोम जेम्स के साथ कार से उसके ससुराल रतलाम में मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची। एसआईटी के साथ शिलोम जेम्स की पत्नी और साली भी मौजूद थी।

विधायक की कार गुजरी लेकिन एंबुलेंस नहीं जाने दी

● यूपी में मां का शव लेकर 1 किमी पैदल चला बेटा, फिर ऑटो से घर ले गया

हमीरपुर (एजेंसी)। यूपी के हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां यमुना पुल पर मरम्मत के चलते वाहनों की एंट्री बंद है। इसके बाद भी भाजपा विधायक की कार पुल से होकर गुजरी, लेकिन मजदूर की मां का शव लेकर जा रही एम्बुलेंस को रोक दिया गया। बेटों ने पुलिसकर्मियों के हाथ-पैर जोड़े, काफी देर तक मिन्नतें कीं, लेकिन पुलिसकर्मी एम्बुलेंस को भेजने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद बेटे ने स्ट्रेचर सहित एम्बुलेंस से शव को उतारा और करीब 1 किमी पैदल चलकर पुल पार किया। स्ट्रेचर को एक तरफ बेटा, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस ड्राइवर और चिकित्सा कर्मी पकड़े हुए थे। इसके बाद शव को ऑटो से लेकर घर गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है मामला

कानपुर-सागर हाईवे एनएच-34 का है। कानपुर-सागर (एनएच-34) पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत का काम शनिवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ। इसके चलते पुल से वाहनों की आवाजाही दो दिन के लिए रोक दी गई। शनिवार सुबह 6.44 बजे सदर विधायक मनोज प्रजापति की कार को पार कराने के लिए यमुना पुल पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई। इसके तीन घंटे बाद सुबह 9.30 बजे टेढ़ा गांव निवासी बिंदा अपनी मां शिवदेवी के शव को लेकर लौटे।

फाइटर जेट की रिपेयरिंग में भारत की मदद लेगा ब्रिटेन

● केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में खड़ा है एफ-35 जेट

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़े ब्रिटिश रॉयल नेवी के स्टील्थ एफ-35 फाइटर जेट ने सभी की नजरें अपनी ओर खींची हैं। यह विमान 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए यहां पहुंचा और तभी से लगातार अपने देश से सहायता आने की उम्मीद में खड़ा हुआ है। ब्रिटेन की तरफ से शुक्रवार को बयान जारी करके कहा गया है कि वह इसकी मरम्मत के लिए भारतीय मदद को स्वीकार कर रहे हैं। इसकी मरम्मत के लिए इसे स्थानीय रखरखाव, मरम्मत

और ओवरहॉल सुविधा केंद्र में ले जाया जाएगा। इससे पहले रॉयल एयरफोर्स ने भारतीय हैंगर का उपयोग करने से इनकार कर दिया था।

मजीठिया की गिरफ्तारी पर अपनों ने ही उठाया सवाल

घिर गई मान सरकार, विधायक को 5 साल के लिए किया सस्पेंड

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पूर्व आईपीएस अधिकारी और अमृतसर नॉर्थ से आम आदमी पार्टी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति ने यह कठोर कदम कुंवर विजय प्रताप की पार्टी विरोधी गतिविधियों और पंजाब सरकार की ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में बाधा डालने के आरोपों के चलते उठाया है। मजीठिया को 25 जून को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अमृतसर में उनके घर से गिरफ्तार किया था। मजीठिया पर 540 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। कुंवर विजय प्रताप ने मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई और उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मजीठिया जेल में थे तब पंजाब सरकार ने कोई पूछताछ नहीं की और

उनकी जमानत में सहायता की लेकिन अब अचानक कार्रवाई शुरू करना सवाल उठाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मजीठिया की पत्नी के साथ विजिलेंस टीम की बहस का वीडियो साझा करते हुए सरकार की कार्रवाई को अनुचित बताया था। इस मुद्दे को उठाने से आम आदमी पार्टी को अपनी कार्रवाई पर जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। उन्होंने गिरफ्तारी के तरीकों को लेकर के भी पार्टी की नियत पर सवाल खड़े किए थे। इसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना और राजनीतिक मामलों की कमेटी ने कड़ा कदम उठाते हुए कुंवर विजय प्रताप को 5 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। कुंवर विजय प्रताप सिंह ने बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, जब मजीठिया 2022 में नशा मामले में जेल में थे।

राज्यपाल ने एकलव्य विद्यालय के बच्चों के साथ सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात

प्रधानमंत्री मोदी जी की बातों से विद्यार्थियों को मिलता है उत्साह और प्रेरणा : राज्यपाल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की मन की बात ज्ञान की बातों का कार्यक्रम है। इसमें ज्ञान और संस्कार की बातें होती है। देश के कोने-कोने में हो रहे प्रेरक कार्यों और प्रसंगों की जानकारी होती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बातों से विद्यार्थियों को नया उत्साह और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतें बड़े बदलाव का कारण बनती है। कार्यक्रम ज्ञान की बातों का खजाना है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम सुनना आदत बनाई जाए। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के सभी छात्र-छात्राओं और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9 से लेकर 12 वीं तक के सभी विद्यार्थी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में शामिल हो। कोई छात्र-छात्रा कार्यक्रम से वंचित नहीं हो।

राज्यपाल श्री पटेल ने यह बात भोपाल में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा में कहीं। राज्यपाल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को बच्चों के साथ सुनने के लिए पहुँचे थे। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने विद्यालय के बालिका छात्रावास का निरीक्षण भी किया।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की मन की बातें गागर में सागर के समान होती है। उसमें अच्छे जीवन के मंत्र होते हैं। उत्कृष्ट कार्यों का बखूबी जिक्र होता है। नवाचार और सफलता के किस्से होते हैं। विभिन्न विषयों की वृहद जानकारियां अल्प अवधि में उपलब्ध हो जाती है, जो हमें जीवन की सही दिशा दिखाती है। अनेक चुनौतियों और समस्याओं के समाधान भी हमें कार्यक्रम में मिल जाते हैं।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में ग्रामीण आजीविका, विकास और जन कल्याणकारी कार्यों का विवरण मिलता है। अत्यंत प्रेरणादायी और मार्गदर्शी विकास की नई पहल और सफलता की कहानियों का पता चलता है। उन्होंने प्रदेश की समस्त पेसा ग्राम सभाओं के पदाधिकारियों से अपील की है कि प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम प्रसारण दिवस पर ग्राम सभाओं का आयोजन करने का प्रयास करें। कार्यक्रम में सहभागिता से ग्राम सभा सदस्यों को ग्राम विकास और कल्याण प्रयासों का दिशा का दर्शन होगा। विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा मिलेगी।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सार्थक ज्ञान वही है जो संस्कार युक्त हो। उच्च शिक्षित होना पर्याप्त नहीं है। अच्छा जीवन जीना महत्वपूर्ण है, जिसमें दायित्व का बोध हो। उन्होंने कहा कि संस्कारित जीवन के लिए बचपन से ही प्रयास किए जाना जरुरी है। उन्होंने आवासीय विद्यालय के शिक्षकों, प्रबंधकों और विद्यार्थियों को मिलकर संकल्प के साथ इस दिशा में प्रयास करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिन की अच्छी शुरुआत, अच्छे जीवन का सबक है। सूर्योदय के साथ प्रातः विधि के बाद कक्ष की सफाई और उसे सुव्यवस्थित करें। उसके बाद स्नान ध्यान कर नाश्ते के बाद अध्ययन प्रारम्भ करना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पहुँचने पर जनजातीय नायक एकलव्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। राज्यपाल का तुलसी का पौधा और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। जनजातीय कलाकृति स्मृति स्वरूप भेंट की गई। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत की संगीतमय प्रस्तुति दी।

स्वागत उद्बोधन अपर संचालक जनजातीय कार्य श्री सुधीर कुमार जैन ने दिया। उन्होंने बताया कि देश के 690 एकलव्य विद्यालयों में 63 विद्यालय मध्यप्रदेश में है। विद्यालय में संचालित नीट, जे.ई.ई. परीक्षा तैयारी कार्यक्रम के 63 बच्चें नीट में और 6 बच्चें जे.ई.ई. में चयनित हुए है। आभार प्रदर्शन विद्यालय के प्राचार्य श्री अमृत झारिया ने किया।

'मन की बात' देश की आत्मा से जुड़ाव का माध्यम, प्रेरणा, दिशा और विश्वास का स्रोत : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

रीवा में प्रधानमंत्री श्री मोदी की 'मन की बात' का किया श्रवण

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि 'मन की बात' सिर्फ संवाद नहीं, यह देश की आत्मा से जुड़ाव का माध्यम है – प्रेरणा, दिशा और विश्वास का स्रोत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का मार्गदर्शन सदैव प्रेरणादायक होता है। 'मन की बात' की 123वीं कड़ी ने जन-मन में नई ऊर्जा का संचार किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों, योग और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों के साथ-साथ आपातकाल की विभीषिका को भी याद किया। आपातकाल का दौर लोकतंत्र के लिए एक काली रात था, जिसे देशवासियों ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से समाप्त किया। यह हमारी लोकतांत्रिक चेतना की अमिट मिसाल है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा के बूथ क्रमांक 111 स्थित निवास में प्रधानमंत्री श्री मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' का श्रवण किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश के बालाघाट की बेटी सुश्री सूमा उइके, जिन्होंने स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मशरूम उत्पादन, पशुपालन और 'दीदी केंटीन' जैसे उद्यमों से

आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में सुश्री सूमा उइके का उल्लेख प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। साथ ही यह अन्य महिलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि भारत का 'ट्रेकोमा मुक्त' घोषित होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की सतत मेहनत का परिणाम है वरन् यह 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'जल जीवन मिशन' की सामूहिक सफलता का भी परिचायक है। यह जनसहभागिता आधारित स्वास्थ्य सुधार मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 'फिटनेस के लिए 10 प्रतिशत तेल कम' जैसे छोटे लेकिन प्रभावशाली सुझाव हर घर को स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाने का सरल मंत्र हैं। फिटनेस और वेलबीइंग के लिए यह सतर्कता, न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे राष्ट्र को सशक्त बनाती है। 'योग फॉर वन अर्थ, वन हेल्थ' की भावना को वैश्विक मंच पर जिस गरिमा से प्रस्तुत किया गया, वह भारत की प्राचीन जीवन पद्धति की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विस्तार, लाखों लोगों की सहभागिता और विशाखापत्तनम से हिमालय तक की प्रेरक झलकियाँ, भारत की 'जनभागीदारी से जनस्वास्थ्य' की दिशा में अद्वितीय यात्रा को दर्शाती हैं।

पति के दोस्त ने महिला से किया रेप

शादी का वादा कर पति से कराया अलग ; अब अपने घर से भी निकाला

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 30 साल की महिला से रेप का मामला सामने आया है। जहांगीराबाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर लिव-इन पार्टनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

महिला विवाहित है। उसके पति के दोस्त का घर आना-जाना था। इसी दौरान महिला की आरोपी से नजदीकियां बढ़ गईं। पहली बार 6 मई 2022 को आरोपी ने पीड़िता के साथ उसी के घर में संबंध बनाए। बाद में शादी का झांसा दिया और पति से अलग होने को कह दिया। बीते ढाई साल से पीड़िता आरोपी के साथ गौतम नगर थाना क्षेत्र में रह रही थी।

इस दौरान कई बार आरोपी ने उसके साथ रेप किया। महिला ने निकाह करने के लिए जोर दिया तो आरोपी ने उसे घर से निकाल दिया। शनिवार को पीड़िता के शिकायत आवेदन की जांच के बाद गौतम नगर पुलिस ने जीरो पर रेप की एफआईआर दर्ज की। रविवार को केस डायरी को जहांगीराबाद पुलिस को सौंप गया, जहां असल कायमी कर ली गई है। टीआई आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि 30 साल की महिला वर्ष 2022 तक इलाके में रहती थी। वह गृहिणी थी, जबकि उसका पति ड्राइवरी करता था। पति का दोस्त शरीफ कुरैशी भी ड्राइवरी करता है और उसका महिला के घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर पति की गैर मौजूदगी में पहली बार आरोपी ने पीड़िता के जहांगीराबाद स्थित घर में रेप किया। बाद में पहला फुसलाकर पति से अलग होने के लिए राजी किया और महिला को अपने साथ गौतम नगर इलाके में किराए के कमरे में रख लिया।

मारपीट करता था आरोपी युवक

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब भी वह आरोपी से शादी के संबंध में बात करती थी। वह उसे मारता और पीटता था। यहां तक की जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी की आए दिन की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी युवक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

बैरसिया में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भक्तों ने रथ की रस्सी खींची

भोपाल। मारुति सत्संग मंडल बैरसिया के तत्वाधान में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा नगर के प्राचीन जगदीश मंदिर बृहस्पति मोहल्ला से प्रारंभ हो कर नगर के मुख्य मार्गो से होती हुई राम जानकी मंदिर महाराणा प्रताप नगर बैरसिया में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ स्वामी की विशेष पूजा अर्चना महा आरती प्रसाद वितरण एवं भंडारे के साथ संपन्न हुई।भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। रथ यात्रा का नगर के अनेक धार्मिक राजनैतिक सामाजिक संगठनों के अलावा नगर की जनता ने पुष्प बर्षा कर स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ स्वामी का आकर्षक रथ रथ को खींचते हुए श्रद्धालु भजन करती कीर्तन मंडलीय मंगल गान करती महिलाएं करतब दिखाते शांति निकेतन स्कूल अखाड़ा मंडली के छात्र छात्राएं ढोल एवं डी जे की धुन पर नृत्य करती युवाओं की टोली एवं चलित झांकियां आकर्षण का केन्द्र रहे। इस अवसर पर नगर के भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवान सिंह मीणा वरिष्ठ समाज सेवी दीपक दुबे हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष सुनील धाकड़ रामलीला कमेटी अध्यक्ष गणेश गिरी गुड्डा भैया हेमराज साहू शांति लाल श्रीवास सहित बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनता मौजूद थी।

प्रॉपर्टी डीलर से 25 लाख की रंगदारी मांगी : नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी ; दोस्त ही निकला दुश्मन, अरेस्ट

भोपाल (नप्र)। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने कॉल पर फरियादी को रंगदारी देने के लिए धमकाया। नहीं देने की हालत में हत्या की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।

मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तब खुलासा हुआ कि आरोपी और फरियादी पुराने दोस्त हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। टीआई अनुराग लाल ने बताया कि मयूर बिहार कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद मतीन पूर्व में ऑटो डील करते थे। लंबे समय से वह प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हैं।

ऑटो डीलिंग कार्य करने के दौरान आरोपी मोहम्मद फैज उनका पार्टनर हुआ करता था। कारोबार में नुकसान के बाद दोनों अलग हो गए। अब फैज मतीन की तरक्की देखकर उससे रंजिश रखने लगा था।

सरेराह युवक की गोली मारकर हत्या

बर्थडे पार्टी के दौरान बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग ; आरोपियों पर 30 हजार का इनाम

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इस दौरान दो बाइक से आए 6 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। दो गोलियां युवक के सिर और पेट में लगी। उसकी मौत हो गई। घटना छोला मंदिर थाना क्षेत्र के लीलाधर कॉलोनी में शनिवार देर रात की है। मृतक का नाम अमित वर्मा (22) है। हत्या का आरोप कुख्यात बदमाश नसीम बन्ने खां और उसके साथियों पर हैं।

अमित वर्मा, मृतक

नसीम स्वयं को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताता है। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हमलावर राजा खटीक नाम के बदमाश की हत्या करना चाहते थे। राजा वारदात के समय अमित के साथ था। इधर, पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रू. 30000 का इनाम घोषित किया।

सड़क पर बातचीत कर रहे थे सभी दोस्त– अमित पिता राधेश्याम वर्मा (22) बरखेड़ी फाटक गली नंबर दो खटीकपुरा में रहता था। वह एक गार्मेंट्स शॉप में नौकरी करता था। लीलाधर कॉलोनी में उसके दोस्त आशू खटीक का जन्मदिन था। सेलिब्रेशन करने वह दोस्तों के साथ आशू के घर शनिवार रात करीब 12 बजे पहुंचा था। यहां सभी दोस्तों ने केक कटिंग की। इसके बाद सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे।

भाई बोला– 6 राउंड गोलियां चलाईं– मृतक के भाई अतुल वर्मा ने बताया कि भाई केक कटिंग के बाद दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था। तभी बदमाश नसीम बन्ने खां और उसके साथी दो बाइकों पर सवार होकर आए 6 लोगों ने अचानक हंगामा किया। नसीम और उसके अन्य साथियों ने करीब 6 राउंड फायर किए। वारदात के बाद बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए।

बदमाश की हत्या करना चाहते थे आरोपी

टीआई सुरेश चंद्र नागर ने बताया कि नसीम और लीलाधर कॉलोनी में रहने वाले राजा खटीक की लेन-देन विवाद पर पुरानी रंजिश है। राजा की हत्या के इरादे से नसीम और साथी आए थे। नसीम ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे गोली अमित को लगी और उसकी जान चली गई।

राजा वारदात के समय अमित और उसके दोस्तों के साथ ही था। आरोपी नसीम और वसीम पर नामजद केस दर्ज किया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टियां रवाना की हैं।

पहले टेंट कारोबारी को भी मारी थी गोली

नसीम बन्ने खां मूल रूप से शाजापुर जिले का रहने वाला है। लंबे समय से भोपाल में रहकर सक्रिय रूप से अपराध कर रहा है। 3 दिसंबर 2023 को भोपाल के बुधवारा में नसीम बन्ने खां ने साथियों के साथ नवाज रियाज (30) को ताज टेंट हाउस में घुसकर गोलियां मारी थीं।

उसके साथियों ने नवाज पर तलवार से हमला किया था। हमले से पहले नसीम ने नवाज को एक ऑडियो वाट्सएप पर सेंड भी किया था। इसमें उसने स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा बताकर कारोबारी से दस लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर बताए समय पर ही कारोबारी को गोली मार दी थी। इस केस में फरारी के दौरान नसीम ने एक रील जारी कर दौराहा थाने में पदस्थ रहे एक टीआई की हत्या करने की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी ने भागने का प्रयास किया तब उसका शार्ट एनकाउंटर किया गया। गोली नसीम के पांव में लगी थी।

नसीम पर 46 केस दर्ज, 40 हजार का इनाम भी रहा

दो साल पहले तक आरोपी नसीम पर 30 हजार रुपए का इनाम सीहोर पुलिस और 10 हजार का इनाम भोपाल पुलिस ने घोषित कर रखा था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी, लूट और डकैती का प्रयास, अड़ीबाजी जैसे 46 केस दर्ज हैं। नसीम पहले भी पुलिस की कस्टडी से फरार हो चुका है। वह सीहोर, राजगढ़ और भोपाल में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता आया है।

प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले की सूमा उइके की पहल को सराहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का माना आभार

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट जिले के कटंगी ब्लॉक की सूमा उइके का उल्लेख करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार, महिलाओं- युवाओं -गरीबों और किसानों के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें

आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में समर्पित भाव से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में राज्य के इन प्रयासों का उल्लेख करने से प्रदेशवासियों का उत्साह बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि बालाघाट जिले के कटंगी विकासखंड के ग्राम भजियापार की सूमा उइके ने स्व सहायता समूह से जुड़कर मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली और आय बढ़ने पर थर्मल थेरेपी और दीदी केंटीन से आय अर्जित कर रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयनगर लालघाटी क्षेत्र में श्री रमेश विजयवर्गीय के निवास पर श्रवण किया।

राजीव सिंह ने राजा भभूत सिंह के योगदान को गीतों में पिरोया, कोरकू कलाकारों की प्रस्तुति

भोपाल। गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय के सभागार में रविवार को कोरकू जनजाति के महान नायक, प्रकृति प्रेमी और वीर राजा भभूत सिंह के योगदान को वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव सिंह ने अपने गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राजा भभूत सिंह को याद करते हुए बैतूल के उमर बारस्कर एवं साथियों द्वारा कोरकू जनजातीय गदली-थापटी नृत्य तथा शिवानी एवं जनजातीय कलाकारों द्वारा कोरकू जनजातीय चिल्लुड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पूर्व संस्कृति संचालानालय के संचालक एन.पी. नामदेव, महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी एवं मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय, भोपाल के क्यूरेटर अशोक मिश्रा ने कलाकारों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

प्रथम प्रस्तुति कोरकू जनजातीय के राजा भभूत सिंह की वीरता, सुशासन और पर्यावरण पर केंद्रित थी। इस संगीतमय प्रस्तुति में गंगा, नर्मदा पर आधारित गीतों को राजीव सिंह ने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया।

कोरकू जनजातीय नृत्य गदली थापाटी - कोरकू नृत्य की वेशभूषा अत्यधिक सादगीयुक्त और सुरूचिपूर्ण होती है। पुरूष सफेद रंग पसंद करते हैं, सिर पर लाल पगड़ी और कलंगी पुरूष नर्तक खास तौर से लगाते हैं। स्त्रियाँ लाल, हरी, नीली, पीली रंग की किनारी वाली साड़ी पहनती है। स्त्री के एक हाथ में चिटकोला तथा दूसरे हाथ में रूमाल और पुरूषों के हाथ में घुंघरूमाला तथा पंछा होता है। कोरकू नृत्यों में ढोलक की प्रमुख भूमिका होती है। ढोलक की लय और ताल पर कोरकू हाथों और पैरों की विभिन्न मुद्राओं को बनाते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं।

कोरकू जनजातीय नृत्य चिल्लुड़ी - यह कुँआर के महीने में कुँवारी युवतियों द्वारा किया जाने वाला समूह नृत्य है। इस नृत्य में बारह से सोलह लड़कियाँ भाग लेती हैं। युवतियाँ एक दूसरे की भुजा पकड़कर वृत्ताकार में नाचती हैं। इस नृत्य में गाये जाने वाले गीतों को 'चिल्लुड़ी सिरिंज' कहते हैं। इस नृत्य में किसी भी वाद्य का उपयोग नहीं होता है।

एम्स भोपाल के डॉ. पंकज मिश्रा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय स्पाइन फेलोशिप से सम्मानित

भोपाल। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता और ज्ञान-साझाकरण की संस्कृति को सदैव बढ़ावा देते रहते हैं। प्रो. सिंह से प्रेरित होकर संकाय सदस्य विभिन्न शोध कार्यों में असाधारण प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, आर्थोपेडिक्स विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉ. पंकज मिश्रा को डेनमार्क की आरहस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित एसआईसीओटी स्पाइन फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इस फेलोशिप के दौरान डॉ. मिश्रा ने रीढ़ की हड्डी से संबंधित उन्नत उपचार पद्धतियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस क्षेत्र के वैश्विक विशेषज्ञों के साथ गहन संवाद किया। उन्होंने इस अवसर पर एम्स भोपाल में किए गए अपने शोध कार्य और चिकित्सा सेवाओं की प्रस्तुति भी दी। डेनमार्क में अपने प्रवास के दौरान डॉ. मिश्रा ने बेहतर मरीज देखभाल के वैश्विक दृष्टिकोणों पर चर्चा की और आधुनिकतम उपचार विधियों के बारे में ज्ञान साझा किया। इस अनुभव से एम्स भोपाल में रीढ़ की बीमारियों के उपचार की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सहायता

मिलेगी। इसके पश्चात डॉ. मिश्रा को स्विट्ज़रलैंड की बेसल यूनिवर्सिटी में भी स्पाइन फेलोशिप के लिए आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने रीढ़ रोगों की अत्याधुनिक चिकित्सा विधियों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया। यह अनुभव उनके वैश्विक दृष्टिकोण को और समृद्ध करता है तथा एम्स भोपाल के ऑर्थोपेडिक विभाग की सशक्तता को दर्शाता है।

कुछ माह पूर्व ही डॉ. पंकज मिश्रा को वियना में यूरोस्पाइन फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था, जो उनकी विशेषज्ञता और समर्पण का प्रमाण है। इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप न केवल नवीनतम तकनीकों को सीखने का अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि विश्वभर में रोगियों की देखभाल के विभिन्न तरीकों को समझने का मंच भी देती हैं। इन फेलोशिप्स के माध्यम से अर्जित अनुभव व ज्ञान डॉ. मिश्रा के माध्यम से अब एम्स भोपाल के मरीजों को सीधे लाभ पहुंचाएगा, विशेष रूप से जटिल स्पाइन रोगों के उपचार में। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) अजय सिंह ने कहा- यह एम्स भोपाल के लिए गर्व की बात है कि डॉ. पंकज मिश्रा ने इतने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारे संस्थान का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार की फेलोशिप न केवल व्यक्ति की शैक्षणिक प्रगति को बढ़ावा देती हैं, बल्कि हमारी रोगी देखभाल की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। डॉ. मिश्रा का यह अनुभव हमारे स्पाइन केयर सेवाओं को और अधिक उन्नत बनाएगा।

संपादकीय

बिहार ने रचा इतिहास

अमूमन राजनीति, जातिवाद और भ्रष्टाचार को छोड़कर बाकी मामलों में फिसड्डी समझे जाने वाले बिहार द्वारा एक संदर्भ में इतिहास रचना अपने आप में सुखद है। यहां स्थानीय निकाय चुनावों में राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार मोबाइल फोन के जरिए वोटिंग का सफल प्रयोग किया, जिसे काफी उत्साह से लिया गया। इसे देश में ई-वोटिंग का आगाज माना जा रहा है। हालांकि मतदाताओं के सामने पारंपरिक तरीके से मतदान का विकल्प भी मौजूद था। इस पहल को राज्य चुनाव आयोग द्वारा तकनीक के सहारे लोकतंत्र को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में उठाया गया कद माना जा रहा है। इसमें पूर्वी चंपारण की बिभा कुमारी मोबाइल से वोट डालने वाली देश की पहली मतदाता बनीं। इस उपलब्धि को राज्य चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा करते हुए इसे 'सुविधा, सुरक्षा और सशक्त भागीदारी का प्रतीक' बताया। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार मोबाइल आधारित ई-वोटिंग के लिए पात्र मतदाताओं में से 70.20 प्रतिशत ने इस नई प्रणाली के माध्यम से मतदान किया, जबकि 54.63 प्रतिशत मतदाताओं ने पारंपरिक मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ई-वोटिंग विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए फायदेमंद है, जो किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं और प्रवासी। हालांकि, इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं मतदाताओं को दिया गया जो पहले से पंजीकृत थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है, जिनमें एस्टोनिया एक उदाहरण है। आयोग ने इसके लिए 10 से 22 जून तक एक विशेष अभियान चलाया था। रिटर्निंग ऑफ़िसर की टीमों ने लोगों को ई-वोटिंग के लिए जागरूक किया। हेल्प डेस्क, रैली और पोस्टरों के ज़रिए प्रचार किया गया। गौरतलब है कि राज्य की 6 नगर पंचायतों और नगरपालिकाओं में हुए उपचुनावों में कुल मिलाकर 62.41 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ। इसमे कुल 538 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान शांतिपूर्ण रहा। ये चुनाव पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, नालंदा, कटिहार, अररिया, सहरसा और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में नगर पंचायत और नगर निगम के उपचुनाव कराए गए। मतों की गिनती 30 जून को की जाएगी। आयोग का मानना है कि ई-वोटिंग प्रणाली न केवल समय की बचत करेगी बल्कि मतदान की पारदर्शिता और भागीदारी को भी बढ़ाएगी। बिहार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां मतदान में गिरती भागीदारी चिंता का विषय बनी हुई है। आयोग को उम्मीद है कि इस नई तकनीक के चलते मतदान में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है तो किसी ने भी इस प्रयोग का विरोध नहीं किया है। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उनका रूख क्या रहेगा, यह देखने की बात है। क्योंकि अभी तो राज्य में तमाम विपक्षी दल भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का ही विरोध कर रहे हैं। अगर इन चुनावों के नतीजे भी उनकी अपेक्षा के विपरीत रहे तो नई तकनीक का व्यापक विरोध शुरू हो जाएगा। वैसे इन चुनाव का फिलहाल बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि बिहार में चार बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें तय होगा कि बिहार पर अगले पांच साल फिर कौन राज करेगा? क्या राज्य में नीतीश कुमार युग समाप्त होगा या नहीं? क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को सत्ता सौंपेगी? क्या इस बार चुनाव में ओवैसी की पार्टी कुछ कमाल करेगी? इनके जवाब भी भविष्य में मिलेंगे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे राज्य के राजनीतिक मिजाज का संकेत जरूर देंगे।

महिलाओं के प्रति सम्मान के बिना कैसे आएगी समता?

पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमती सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भी महिलाओं की शक्ति और योग्यता का एहसास कराया है। 1960 के दशक में डॉ. लोहिया ने लिखा था कि हमारे देश में जाति और योनि के दो कटघरे में देश की बड़ी संख्या को कैद कर दिया गया और निर्जीव बना दिया गया है। जिस जमाने में किसी ने नारी सशक्तिकरण जैसा शब्द सुनना तो दूर सोचा भी नहीं होगा, उस जमाने में लोहिया न केवल नारियों को जाति व परंपरा के बंधन से मुक्त कर पुरुष के समकक्ष खड़े करने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने द्रौपदी बनाम सावित्री की बहस को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर द्रौपदी के संघर्षशील पक्ष को उभारा। नारी की क्षमता, योग्यता संघर्ष की प्रतिभा को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया। लोहिया के जीवन काल में इन सवालों पर हलचल तो शुरू हुई परंतु वह शुरुआत भर थी। लोहिया कहते भी थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद, पर सुनेंगे जरूर। आज जब सुनीता विलियम्स से लेकर सोफिया कुरैशी विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के उपलब्धियों के किस्से छपते हैं तब लगता है लोहिया की बात सुनी जा रही है।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

अभी कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार समूची दुनिया ने विश्व महिला दिवस मनाया। भारत में भी यह दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। दुनिया और देश में किस प्रकार महिलाएं आगे जा रही है इसका भी चित्रण किया गया। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अवसर मिलने से महिलाओं की प्रतिभा में निखार आता है। उनकी छिपी प्रतिभाएं सामने आई हैं। हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 माह से अधिक अंतरिक्ष में गुजारे उन सुनीता विलियम्स के साहस और पराक्रम का क्या मुकाबला हो सकता है? यद्यपि पूंजीपतियों में महिलाओं की संख्या अभी कम है।

पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमती सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भी महिलाओं की शक्ति और योग्यता का एहसास कराया है। 1960 के दशक में डॉ. लोहिया ने लिखा था कि हमारे देश में जाति और योनि के दो कटघरे में देश की बड़ी संख्या को कैद कर दिया गया और निर्जीव बना दिया गया है। जिस जमाने में किसी ने नारी सशक्तिकरण जैसा शब्द सुनना तो दूर सोचा भी नहीं होगा, उस जमाने में लोहिया न केवल नारियों को जाति व परंपरा के बंधन से मुक्त कर पुरुष के समकक्ष खड़े करने के लिए संघर्षरत थे। उन्होंने द्रौपदी बनाम सावित्री की बहस को प्रतीकात्मक स्वरूप देकर द्रौपदी के संघर्षशील पक्ष को उभारा। नारी की क्षमता, योग्यता संघर्ष की प्रतिभा को एक नए ढंग से प्रस्तुत किया। लोहिया के जीवन काल में इन सवालों पर हलचल तो शुरू हुई परंतु वह शुरुआत भर थी। लोहिया कहते भी थे कि लोग मेरी बात सुनेंगे शायद मेरे मरने के बाद, पर सुनेंगे जरूर। आज जब सुनीता विलियम्स से लेकर सोफिया कुरैशी विभिन्न क्षेत्रों में नारियों के उपलब्धियों के किस्से छपते हैं तब लगता है लोहिया की बात सुनी जा रही है।

जहां एक तरफ नारियां आगे बढ़ रही है दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार भेदभाव की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यदि आप किसी भी दिन के अखबार को देखें या टीवी चौनल के समाचारों को देखें तो आपको प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सुर्खियों में मिलती हैं जहां नारी शाब्दिक और शारीरिक अन्याय का शिकार होती है। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं। आज आजादी के सात दशक के बाद भी घट रही हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे प्रगतिशील मानस और पीछे देखू मानस में एक सतत संघर्ष चल रहा है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने एक लड़की को न केवल हवस का शिकार बनाया बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी, ताकि कोई प्रमाण न रहे। तंदूर कांड से लेकर हत्याकांड तक ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। अब पिछले एक डेढ़ दशक से केंद्र और कई सूबे में एक दल की सरकार के बाद ऐसी घटनाओं को पंख लग गए हैं। कुछ दिन पहले एक भाजपा नेता ने टीवी चौनल पर किसी को मां की गालियां दीं। आज भी जो गालियां है वह अमूमन नारियों को लेकर हैं। कहीं ना कहीं मस्तिष्क में नारी को कमजोर और छोटा समझने का भाव है। जिन पार्टियों के नेता नारियों के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनकी पार्टियां उनके बचाव में खड़ी हो जाती हैं। मध्यप्रदेश के एक पूर्व-मुख्यमंत्री ने एक बार एक महिला का उल्लेख करते हुए टंचमाल कहा था। सरकारी पार्टी की महिलाएं भी निजी बातचीत में अपने आप को असुरक्षित मानती हैं और असम्मान का शिकार होती हैं। हाल में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि लड़कियां कम वस्त्र पहनती हैं जो उन्हें पसंद नहीं। ऐसा एक जुमला वे पहले भी कह चुके हैं। बच्चियां क्या पहनें, उनकी क्या आवश्यकता है, यह निर्णय भी पुरुष समाज लेना चाहता है।

मुझे याद है जब श्रीमती सानिया मिर्जा का नाम टेनिस खिलाड़ी के रूप में उभरा था तो कई मौलवियों ने उनके खिलाफ टिप्पणियां की थीं। एक प्रकार का घोषित अघोषित फतवा जारी किया था। नारियों के प्रति ऐसी घटनाएं आमतौर पर सभी धर्म में हो रही हैं। जहां भी नारियां प्रतिकार में खड़ी होती हैं, जुल्म का शिकार होती हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ लड़ने वाली हजारों बच्चियों को जेल में रहना पड़ा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पढ़ाई और पढ़ाई की वकालत करने वाली बच्चियों को गोली तक खानी पड़ी। यूरोप के देशों में भी महिलाएं कुछ मुक्त तो हुई हैं परंतु बराबरी पर आज भी नहीं हैं। अगर नर-नारी की समता सही मायने में कहीं देखने मिलती है तो वह आदिवासी समाज में। समाज के मानस की जकड़न कितनी गहरी है उसे हाल में अखबार में आई एक घटना से समझा जा सकता है। कटनी में पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर कार्यरत श्रीमति ख्याति मिश्रा ने अपने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें अपने पति से खतरा है। कुछ दिनों पूर्व पुलिस ने उनके घर में घुसकर उनके माता-पिता आदि से मारपीट की। इसके पीछे उनके पति को बताया जा रहा है जो तहसीलदार हैं। कटनी की घटना के बाद श्रीमती मिश्रा का तबादला मैहर किया गया। उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखकर मैहर में अपनी जान को खतरा बताया है क्योंकि उनके पति वहां रह चुके हैं। श्रीमति ख्याति मिश्रा के अनुसार उनके पति यह बर्दाश्त नहीं कर कर पा रहे कि पत्नी बड़े पद पर पहुंच गई और वे खुद अभी तहसीलदार ही हैं। अपने मन में यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कोई पद पुरुष से बड़ा होता है। उनके बयान के बाद पति ने पत्नी के पुलिस अधीक्षक से संबंध होने का आरोप लगाया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन है। सच्चाई भी है तो इस आधार पर न्यायिक अलगाव की मांग कर सकते थे। पत्नी से अलग रह सकते थे, परंतु उन्होंने यह नहीं किया। आज भी ज्यादातर यही भाव काम कर रहा है कि महिलाओं को पुरुष से नीचे रहना चाहिए। सरकार इसे किस रूप में ले रही है यह अभी स्पष्ट नहीं है। लड़कियों के छोटे कपड़ों के प्रति चिंतित मंत्री की भावनाओं को भी प्रदेश सरकार किस भाव से ले रही है कहना कठिन है। कुछ लोगों का यह भी मानना है की मंत्री का बयान उनके संगठन के इशारे पर दिया गया है जो भारत को सनातन में ले जाना चाहता है। परंपराओं में महिलाओं का पतिव होना, उनका दासी होना, पर्दे में रहना सभी घोषित सामाजिक परंपराएं हैं। कुछ साल पहले भी मंत्री ने एक प्रसंग में कुछ महिलाओं की तुलना शुर्पणखा से की थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत ने भी महिलाओं के जींस पहनने की निंदा की थी। उसे संस्कृति विरोधी बताया था कई बड़े तथाकथित जनप्रतिनिधि या सत्ताधारी नेता कपड़ों को ही बलात्कार का कारण बताते हैं। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें कोलकाता की डॉक्टर लड़की के बलात्कार से लेकर निर्भया तक आए दिन घट रहे अपराधों को उद्धृत किया जा सकता है। यह बड़ा विचित्र और दुखद है कि हाल की घटनाओं के बाद देश के महिला संगठनों द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को लेकर कोई विशेष भूमिका दिखाई नहीं दी।

मेरा यह कहना नहीं है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना केवल महिला का दायित्व है। समूचा पुरुष समाज राजनीति वोट के लिए असहाय है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री के द्वारा सुश्री सोफिया कुरैशी के बारे में दिए गए बयान के बाद भी न मंत्री जी का इस्तीफा हुआ, न उन्हें हटाया गया, न उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसा लगता है कि संघ व संगठन मामले के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री जी भी 3 जून 2025 को भोपाल आए थे जहां मीडिया के अनुसार उन्होंने कई लाख महिलाओं को संबोधित किया था। इस सम्मेलन में वे सरकार की उपलब्धियां को गिनाते रहे। पर एक शब्द भी उन्होंने अपने मंत्रियों के खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया। यानी वे भी यह जानते मानते हैं कि देश में आम मानस अभी भी पुरुष सत्तात्मक का है। इसलिए वे अपने वोट के खेल में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। प्रधानमंत्री की इस स्थिति के वास्तविक कारण क्या हैं? मेरा मानना है कि कारण जो भी हों उन्हें उन कारणों से मुक्ति पाना चाहिए। देश को स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। देश जानना चाहता है कि सोफिया कुरैशी से लेकर कम वस्त्रों तक जो मानसिकता समाज व सत्तापक्ष में उभरी है वे उसे मिटाना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं। क्या उनकी पार्टी सनातन व्यवस्था के नाम पर उस दौर में जाना चाहती है जहां नारी को दोयम दर्जा का माना जाएगा? जहां महिलाएं पुरुषों की दासी बन कर रहें? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सावित्री, पार्वती ऐसी महान नारियों की पूजा करना यह समता नहीं है जो हाथ पाषाण प्रतिमा को पूजते हैं वही जिंदा तन को पीटते हैं। यह सरकार व समाज सभी की जिम्मेदारी है कि नर नारी को समान समझा जाए। उन्हें पूरे अवसर मिलें, आजादी मिले उनकी आजादी का सम्मान हो।

सामयिक

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान के दोहरे पैमाने

आतंकवाद के मसले पर चीन के किंगदाओ नगर में हुई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में एक बार फिर चोर-चोर मौसेरे भाई चीन और पाकिस्तान ने भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में दोगलापन दिखाया है। इस बैठक में सदस्य देशों के रक्षा मंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद के खात्मे के लिए किए जा रहे आवाहन ने वैश्विक स्तर पर ऐसा माहौल बनाने का काम किया है कि इस समस्या को जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन एससीओ की बैठक में जिस दस्तावेज को साझा हस्ताक्षर के लिए सामने लाया गया तब उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल नहीं किया गया। जबकि इस हमले में 26 भारतीय नागरिक आतंकवादियों ने मार दिए थे। इस दस्तावेज में बलूचिस्तान का नाम हैं। जबकि बलूचिस्तान के नागरिक पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्थात इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर दस्तखत करने से साफ इंकार कर दिया। इस संगठन पर चीन का प्रभाव है और चीन ही इस बार संगठन का अध्यक्ष देश है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को न केवल पक्षपातपूर्ण माना, बल्कि इसे पाकिस्तान और उसके हितचिंतक चीन की हरकत माना। अतएव राजनाथ सिंह ने दस्तखत नहीं किए। इस संगठन के दस्तावेज की उपयोगता तभी है, जब बैठक में उपस्थित सभी सदस्य देश मुद्दों पर सहमत होकर हस्ताक्षर करने के साथ साझा बयान भी जारी करें। तब कहीं इस दस्तावेज पर सहमति बन पाती है।

इस संगठन में 10 देश परस्पर जुड़े हितों को मजबूत करने के लिए शामिल हैं। इन देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस और तजाकिस्तान शामिल हैं। 2001 में इस संगठन का गठन हुआ था। आरंभ में चीन और रूस समेत पांच देश इसमें शामिल थे। 2001 में उज्बेस्तिन, 2017 में भारत और पाकिस्तान, 2022 में ईरान एवं 2024 में बेलारुस इस संगठन में भागीदार हुए। इन देशों की कुल जीडीपी में 30 फीसदी और दुनिया की आबादी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यानी इस संगठन की इन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए परस्पर भागीदारी जरूरी है। लेकिन जब राजनाथ सिंह ने दस्तावेज की इबारत को पक्षपात पूर्ण पाया तो उन्होंने खुले षब्दों में कहा, 'भारत आतंकवाद पर दोहरे मापदंड मंजूर नहीं करेगा। आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों की खुली निंदा होनी चाहिए। कुछ देशों ने सीमा पार आतंकवाद को न केवल अपनी नीति ही मान लिया है, बल्कि अपने देश में उन्हें संरक्षण भी देते हैं। बावजूद इस हकीकत को नकारते हैं। ऐसे दोहरे मापदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें अब समझना होगा कि आतंकवाद के अधिकेंद्र (एपीसेंटर) अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं।' नए भारत के इस कड़े संदेश ने उपस्थित रक्षा मंत्रियों को हैरानी में डाल दिया। अतएव न तो कोई सहमति बन पाई और न ही संयुक्त बयान जारी हो पाया। इस परिणाम ने समूची दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब भारत अपने हितों से समझौता करने के लिए कतई तैयार नहीं है।

दरअसल भारत चाहता था कि एससीओ पहलगाम हमले की निदां करे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर स्पष्ट रुख अपनाए। लेकिन चीन की एक बार फिर दगा की दोगली नीति सामने आ गई। एक सदस्य देश ने इस पहलगाम मुद्दे को दस्तावेज में षामिल करने से असहमति जता दी। वस्तुतः राजनाथ सिंह ने कड़ा रुख अपना लिया और दस्तखत नहीं किए। इस साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का बड़ा कारण दस्तावेज न तो निश्पक्ष था और न ही इसमें कोई पारदर्शिता थी। यह भी साफ नहीं किया कि आखिर इस अभिलेख को किन देशों ने तैयार किया है। यह दस्तावेज आतंकवाद से जुड़े तथ्यों के विपरीत था। भारत के जम्मू-कश्मीर प्रांत में 22 अप्रैल को पहलगाम में सैलानियों पर बड़ा हमला हुआ था। इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। आतंकियों द्वारा किया यह हमला मानवता के लिए क्रूरता का चरम था। इसलिए भारत ने इस आतंकी हमले को दस्तावेज में शामिल करने की मांग भी की थी। परंतु इस मांग को नमंजुर कर दिया गया। अध्यक्षता कर रहे चीन का यह रुख पाकिस्तान के प्रति उदारता जताता है, जो सर्वथा पक्षपातपूर्ण है। जबकि बलूचिस्तान की आतंकी गतिविधियों से जुड़ी जफर एक्सप्रेस की घटना इसमें दर्ज थी। इस संगठन का लक्ष्य शामिल देशों की सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के साथ आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर आपराध जैसे मसलों पर सटीक रणनीति बनाकर उस पर संयुक्त पहल करना भी है। लेकिन जिस तरह से पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया गया उससे साफ है कि अध्यक्ष देश की नियत साफ नहीं है।

इस तरह का दोहरा चरित्र इसलिए खतरनाक है कि इसने क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया। जिसके चलते आतंकवाद की समस्या से निपटना जटिल होगा। क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लगातार आतंकी खेल, खेलता हुआ खून की इबारतें लिख रहा है। इस सच्चाई को समूची दुनिया भलीभांति जानती है। क्योंकि भारत आतंक से पिछले ढाई दशक से निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। स्वयं चीन ने बीजिंग में कुछ वर्ष पहले हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के घोषणा पत्र में इस तथ्य को षामिल किया था कि कई बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों से अपनी गतिविधियां चलाते हैं।

पहलगाम में किए निरंकुश हमले में भी पाकिस्तान से आए आतंकियों का हाथ था। बावजूद एससीओ की बैठक के संयुक्त बयान में पहलगाम को नजरअंज करना दोगलापन नहीं तो और क्या है ? एससीओ में आतंकवाद पर शिकंजा नहीं कसना इसलिए और चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वहां अनेक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख हैं। अमेरिका पर आतंकी हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को ही पाकिस्तान ने शरण दी थी। उसका अंत अमेरिकी वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूची में बताया है कि पाक में 136 आतंकवादियों के ठिकाने हैं और यहां 22 आतंकवादी हथियारबंद संगठनों को पाक सेना संरक्षण दे रही है। वाइदवे इन आतंकियों के हाथ परमाणु हथियार लग जाते हैं तो ये मानवता के विरुद्ध कैसी तबाही मचाएंगे, यह कहना अनुमान से परे है। अतएव राजनाथ सिंह ने अभिलेख पर दस्तखत न करके दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत आतंक के विरुद्ध लड़ाई लड़ता रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

लेखक स्तंभकार हैं।

संसदों के अंतर्मंथन का क्षण

जब हम किसी राष्ट्र की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी संसद की छवि उभरती है–वह पवित्र मंच, जहाँ जनता की आकांक्षाएँ, चिंताएँ और अधिकार एक स्वर में गूंजते हैं। संसद केवल कानूनों का कारखाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वह जीवंत हृदय है, जो हर नागरिक की धड़कनों को प्रतिबिंबित करता है। इस जीवंतता को वैश्विक स्तर पर और सशक्त करने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल संसदों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि उनके दायित्वों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा में गहन चिंतन का अवसर है। यह एक ऐसा आह्वान है, जो संसदों को याद दिलाता है कि वे केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि जनता की आवाज़, विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक हैं।

इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से हुई, जब 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यह तारीख संयोगवश 1889 में स्थापित इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) की स्थापना की वर्षगांठ से भी जुड़ी है। आईपीयू वह वैश्विक संगठन है, जिसने 136 साल पहले संसदों को एक मंच पर लाकर वैश्विक संवाद, शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की नींव रखी। इसका नारा–'लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए' और उद्देश्य 'संसदों के माध्यम से विश्व शांति और विकास के लिए हर आवाज़ को सुनना' आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 2025 में इस दिवस की थीम 'संसद और सतत विकास लक्ष्य- लैंगिक समानता और समावेशिता' न केवल समय की मांग है, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को उजागर करती है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि कोई भी लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें हर वर्ग–महिलाएँ, युवा, हाशिए पर पड़े समुदाय, और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग–की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो।आज विश्व संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इन 17 लक्ष्यों में लैंगिक समानता (एसडीजी-5) और मज़बूत, समावेशी संस्थानों का निर्माण (एसडीजी-16) संसदों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी केवल 26 प्रतिशत है (आईपीयू, 2023), जबकि भारत में यह आंकड़ा और भी कम, लगभग 14.4 प्रतिशत (लोकसभा, 2024) है। यह असंतुलन न केवल लैंगिक समानता के लिए चुनौती है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। संसदें नीतियां बनाती हैं, संसाधनों का आवंटन करती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाती हैं। लेकिन अगर इन नीतियों में आधी आबादी की आवाज़ शामिल नहीं है, तो क्या यह लोकतंत्र वास्तव में 'सभी के लिए' है?भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र है। यह वह मंच है, जहाँ 1.4 अरब लोगों की विविधता को एक स्वर में ढाला जाता है। लेकिन इस विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए संसद को और अधिक समावेशी होना होगा। उदाहरण के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी बाकी है। इसी तरह, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे आदिवासियों, दलितों, और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन संसद में युवा सांसदों की संख्या केवल 12 प्रतिशत के आसपास है। यह असंतुलन न केवल नीतियों को प्रभावित करता है, बल्कि युवाओं के बीच राजनीतिक संस्थानों के प्रति विश्वास को भी कम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें उन मूलभूत सवालों से रूबरू कराता है, जो अक्सर संसदीय बहसों के शोर में दब जाते हैं। क्या संसदें जनता के सबसे ज़रूरी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं? क्या वे लैंगिक भेदभाव, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही हैं? आईपीयू की 2022 की वैश्विक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, केवल 40त्न संसदों ने ही सतत विकास लक्ष्यों को अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से शामिल किया है। यह आंकड़ा चेतावनी देता है कि संसदों को अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा। भारत में, उदाहरण के लिए, संसद ने जलवायु परिवर्तन (एसडीजी-13) और शिक्षा (एसडीजी-4) जैसे क्षेत्रों में कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन उनकी निगरानी और कार्यान्वयन में कमी दिखती है।संसदों की जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है। आईपीयू के अनुसार, विश्व की 80 प्रतिशत संसदें अब डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन सत्र, ई-वोटिंग, और नागरिक संवाद मंच। भारत में भी डिजिटल संसद पहल के तहत संसद के सत्रों को डिजिटल रूप से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन नागरिकों की सीधी भागीदारी अभी भी सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संसदें न केवल नीतियां बनाएं, बल्कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। उदाहरण के लिए, न्यूज़ीलैंड और कनाडा जैसे देशों में 'संसदीय ओपन डे' जैसे आयोजन होते हैं, जहाँ आम लोग संसद में जाकर अपने सांसदों से मिल सकते हैं। भारत में भी इस तरह की पहल लोकतंत्र को और जीवंत बना सकती हैं।

इस दिवस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह संसदों को आत्म-मूल्यांकन का अवसर देता है। क्या संसदें वास्तव में समावेशी हैं? क्या वे बदलते समय के साथ तालमेल बिठा रही हैं? आईपीयू की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की केवल 20त्न संसदों में ही लैंगिक समानता और समावेशिता के लिए विशेष समितियाँ हैं। भारत में, हालाँकि संसद में महिला सशक्तीकरण समिति जैसी संरचनाएँ हैं, लेकिन इनका प्रभाव अभी व्यापक नहीं हुआ है। यह समय है कि संसदें न केवल कानून बनाएं, बल्कि स्वयं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए नवाचार करें।नागरिकों की भूमिका भी इस दिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं है; यह जनता की जागरूकता और भागीदारी से जीवित रहता है। हम कितनी बार अपने सांसदों से सवाल पूछते हैं? कितनी बार संसद के सत्रों पर ध्यान देते हैं? भारत में, आरटीआई (सूचना का अधिकार) जैसे उपकरणों ने नागरिकों को सशक्त किया है, लेकिन संसदीय कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी अभी भी न्यूनतम है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक दोतरफा प्रक्रिया है, संसद को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, और जनता को संसद के प्रति जागरूक। 30 जून केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है–एक संकल्प कि संसदें केवल सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली आवाज़ें न बनें, बल्कि समाज के हर कोने तक समानता, न्याय और विकास की गूंज पहुँचाएँ। जब संसदें हर नागरिक की आवाज़ को सुनेंगी–चाहे वह एक महिला हो, एक युवा हो, या समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति–तब ही लोकतंत्र एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली बनेगा। यह दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि संसदें केवल कानून बनाने वाली इमारतें नहीं, बल्कि वे मंदिर हैं, जहाँ मानवता की आकांक्षाएँ आकार लेती हैं। इस 30 जून को हम संकल्प लें कि हमारी संसदें न केवल सशक्त होंगी, बल्कि संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शक भी बनेंगी। यही लोकतंत्र की सच्ची जीत होगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. अतुल चतुर्वेदी

लेखक व्यंग्यकार हैं

एक नोबेल बपु रे दई दो दई

नोबेल पुरस्कार की कामना एक सतत और चिर प्रतीक्षित कामना है। साहित्य के साधकों को तो कई बार ज्ञात भी नहीं होता वे चुपचाप एकला चलो रे के साधना कर्म में लगे रहते हैं लेकिन राजनीतिज्ञों की कार्य शैली अलग तरह की होती है और उसमें भी महामहिम की तो है ही ढिंढोरा पीटन शैली। महामहिम कोई काम शांति और सिस्टम से करने के लिए जन्मे ही नहीं हैं। वो तो धूमकेतु के अपडेटेड वर्जन हैं। उत्पात के अवतार हैं। जो करेंगे ढोल बाजों के साथ। प्रचार की दुनिया के आदमी हैं। आदमी भी ख़ासे दिलचस्प और मजाहिया किस्म के। आज आपके साथ हैं, आपके प्रशंसक हैं क्या पता कल आपके जानी दुश्मन हो जायें। आज आपके बच्चे उनके आँगन में खेल रहे हैं क्या पता कल आपके कपड़े फाड़ने की नौबत आ जाये।

कई बार पता ही नहीं चलता कि अमुक व्यक्ति किसी सर्कस में मसखरे की भूमिका में है या दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की भूमिका में। पद को इतना सुपद और अवपदित कर दिया है कि आम जन और मीडिया भौंचक है। मजेदार बात यह है कि पहले हम दो विरोधी देशों को हथियार बाँटते हैं फिर वे हथियारों की फूंक में एक दूसरे से लड़ते हैं और अंततः हम महामहिम दोनों में समझौता करवाते हैं। समझौता भी लॉलीपॉप देने का लालच देने के लिए होता है। अब उनको इस युद्ध विराम के लिए नोबेल शांति की आकांक्षा है।

यह तो साठ की दशक की फ़िल्मों सा टुटका हुआ जब हीरो स्वयं गुंडों से आक्रमण करवा कर हीरोइन को इंप्रेस कर देता था। पहले हथियार बाँटो फिर युद्ध रुकवाओ और आखिर में नोबेल शांति की लॉबिंग करो। आखिर शांति के लिए उनके प्रयासों को कौन नहीं जानता? अफ़ग़ानिस्तान, ईराक और पहले वियतनाम तक में उनका देश शांति की पहल ही करता रहा है। नोबेल शांति एक ऐसी चिड़िया है जिसको अपने पिंजरे में क़ैद कर आँगन में सजाने की कामना हर राजनेता की रही है। हमारे देश के भी अनेक पी एम इसकी लाइन में लगे रहे और अब दुनिया के दूसरे बड़े लोकतंत्र के शासनाध्यक्ष इसके लिए दर्दीला बयान जारी कर रहे हैं।

उनकी तुनक मिजाजी के चर्चे कम नहीं हैं। उनका इतिहास ज्ञान भी अद्भुत है, उनकी नवीनतम शोध से ही पता चला कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए हजारों साल से लड़ रहे हैं। दो दिन पूर्व तक वो युद्ध रोकने की बात करते हैं और फिर उनका मूड अचानक बदल जाता है और युद्ध में कूद पड़ते हैं। हमारे देश से तो उनको गहरा लगाव है वे हमारे प्रिय मेहमान भी रहे हैं और हमने उनका दुर्दिनों में साथ भी दिया है प्रचार कर के लेकिन उनको देखकर हमारे रहनुमा जी यही गुनगुनाते होंगे – अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भारत पर टैरिफ बढ़ा कर और चीन को पहले धमका कर फिर घुटने टेक कर उन्होंने विलक्षण साहस का परिचय दिया है। इस तरह उन्होंने ट्रेड वार को भी रोकने की महान कोशिश की है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल भी उनके नाम बनता तो है। शांति नहीं तो अर्थशास्त्र का ही दे दो महामहिम जी को। कितना व्यापार फल फूल रहा है दुनिया में उनकी बदौलत आखिर!

नोबेल का दर्द अनोखा दर्द है। इसकी पीर हर कोई नहीं जानता? जिनको नोबेल मिलना था उन्होंने कभी इस ओर नहीं झांका। चाहे गांधी रहे हो या लियो टॉलस्टॉय। लेकिन राजनेता महत्वाकांक्षी जीव होता है उसका परिणाम में विश्वास होता है त्याग में नहीं। इधर युद्धविराम करवाया उधर नोबेल शांति दे दो।

लगता है नोबेल नादिया किनारे बना एक बंगला है और सुदूर से आवाज आ रही है युद्ध के मुहाने इक नोबेल बपु रे दई दो दई हजारों बेगुनाह नागरिकों और बच्चों की हत्या को नज़रअंदाज़ कर के भी उनको एक नोबेल चाहिए अदद। ताकि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में उनका नाम सुरक्षित हो सके। सच मानव मन कितना भोला और निश्छल होता है!

युद्ध की घोषणा के बारे में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा पूरी तरह से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। वास्तविक निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 53(2) घोषित करता है, कि पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किया जाता है।

गंभीर सैन्य तनाव के तहत पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन स्थानों की सफलतापूर्वक रक्षा की और खतरों को बेअसर कर दिया। जवाब में, भारत ने प्रमुख पाकिस्तानी शहरों इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट को निशाना बनाकर जोरदार जवाबी कार्रवाई की। यह तीव्र सीमा पार आदान-प्रदान भारत द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किए जाने के बाद हुआ। जिसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ स्थानों पर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। फिलहाल युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन इस संदर्भ में यह जानना जरुरी है कि कोई युद्ध छिड़ने पर भारतीय संविधान युद्ध की घोषणा के संबंध में क्या कहता है! ऐसी स्थिति में युद्ध की औपचारिक घोषणा आवश्यक है अथवा नहीं, यह आम लोगों में भी स्वाभाविक जिज्ञासा है।

भारत में युद्ध की घोषणा करने के लिए कोई औपचारिक, एकल कानून नहीं है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में है। इसके बजाय, ऐसे मामलों को संवैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। राष्ट्रपति इसकी सलाह पर कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। हालांकि, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 53(2) घोषित करता है कि पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग कानून द्वारा विनियमित होगा। युद्ध की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन, इसका प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर किया जाता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह घोषित करता है कि (1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के निर्वहन में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर सामान्यतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (2) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई थी और यदि दी गई थी तो क्या, किसी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 निर्दिष्ट करता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। फिर भी अनुच्छेद 74 के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है।इसलिए, राष्ट्रपति द्वारा युद्ध या शांति की कोई भी औपचारिक घोषणा पूरी तरह से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। वास्तविक निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं।

मंत्रिमंडल रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सैन्य प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट को ध्यान में रखता है। व्यवहार में, युद्ध में जाने या शांति की घोषणा करने का निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल (मंत्रिपरिषद) द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस प्रक्रिया में मंत्रिमंडल को महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले, मंत्रिमंडल सैन्य प्रमुखों, खुफिया एजेंसियों और राजनयिक चैनलों से इनपुट ले सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं, जो राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार हैं। 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल (जो युद्ध की स्थिति में लागू होता है) की घोषणा केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर कर सकते हैं।

संसद को युद्ध की घोषणा को पहले से मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह निगरानी, वित्तपोषण और सरकार को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद रक्षा बजट की निगरानी करती है और उसे सैन्य कार्रवाइयों पर बहस करने का अधिकार है। हालांकि, संसद संवैधानिक रूप से युद्ध की घोषणा या पूर्व-अनुमोदन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह निगरानी और वित्तपोषण में भूमिका बनाए रखती है। यह रक्षा बजट की निगरानी करती है, इसके पास सैन्य कार्रवाइयों पर बहस करने और सरकार को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। लंबे समय तक सैन्य मुठभेड़ों के दौरान सरकार से संसद को सूचित करने और राजनीतिक सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है।

यद्यपि प्रारंभिक युद्ध घोषणा राष्टपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है, फिर भी इसे अनुमोदन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। युद्ध की घोषणा करने के बारे में कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक अनुच्छेद नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की प्रक्रिया युद्ध जैसी स्थिति के दौरान भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे करीबी औपचारिक विधि है। ''प्रक्रियात्मक रूप से कहें तो, यदि युद्ध की औपचारिक घोषणा की जानी है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, स्थिति का आकलन करने के बाद, राष्ट्रपति को एक लिखित सिफारिश करेगा। मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत ''युद्ध'' या ''बाहरी आक्रमण'' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं।

आपातकाल की यह घोषणा पूरे देश या किसी विशिष्ट भाग पर लागू की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए। यह एक महीने के बाद लागू नहीं होगी जब तक कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत) से पारित प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न हो जाए। एक बार अनुमोदित के बाद, आपातकाल छह महीने तक सक्रिय रहता है और हर छह महीने में संसद की मंजूरी से इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी बाद की घोषणा के माध्यम से आपातकाल की घोषणा को रद्द कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 44 वें संशोधन में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि लोकसभा आपातकाल को जारी रखने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करती है तो राष्टपति को आपातकाल को रद्द करना होगा। लेकिन, युद्ध की घोषणा करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है।

इन सबके बावजूद, भारत के संविधान में युद्ध की घोषणा के लिए कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है। हालांकि, भारतीय संविधान में युद्ध की घोषणा के लिए समर्पित कोई विशेष अनुच्छेद या प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों को युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थितियों में लागू किया जाता है। भारत ने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं की गई। सन् 1962 भारत-चीन युद्ध, चीन ने अचानक हमला किया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध विवादित सीमा पर बड़े पैमाने पर चीनी आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। भारत इस हमले से हैरान था। भारत या चीन की ओर से युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। चीन ने एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा की और लगभग एक महीने बाद वापस चला गया।

सन् 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध, सीमा पर तनाव और पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से बढ़ा। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध सीमा पर झड़पों और कश्मीर में पाकिस्तान के ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम से बढ़ा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जवाबी कार्रवाई की। फिर से, बड़े पैमाने पर शत्रुता से पहले युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। संघर्ष संयुक्त राष्ट की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम और ताषकंद घोषणा के साथ समाप्त हुआ। सन् 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध (बांग्लादेष मुक्ति युद्ध), पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने के बाद भारत ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने पहले हमला किया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में राजनीतिक संकट और मानवीय संकट से उपजा था। शरणार्थियों की बड़ी संख्या में आमद के बाद भारत ने बंगाली मुक्ति आंदोलन के समर्थन में हस्तक्षेप किया।

हालांकि संघर्ष व्यापक था, लेकिन भारत की सैन्य भागीदारी से पहले युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हवाई हमले शुरू किए, जिसके कारण भारत ने युद्ध में पूरी तरह से प्रवेष किया। सन् 1999 कारगिल युद्ध, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया। युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं। यह संघर्ष कारगिल क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ से शुरू हुआ। भारत ने ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया, जो कि एक सीमित संघर्ष था और दोनों पक्षों द्वारा युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। इस कारण वर्तमान संदर्भों में भी औपचारिक रूप से युद्ध की कोई घोषणा आवश्यकता नहीं थी।

कहीं हम 'गुणवत्ता' को आंकड़ों में तो नहीं खो रहे?

शिक्षा प्रणाली

मनीष जैसल

स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली बीते कुछ दशकों में जिस गति से विस्तारित हुई है, उसमें गुणवत्ता की निगरानी एक जटिल कार्य बन गया है। यही कारण था कि वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नेक) की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अकादमिक गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड प्रदान करना रहा है। परंतु तीन दशकों के बाद यह विचार करना आवश्यक है कि क्या यह संस्था वास्तव में उस उद्देश्य को पूर्ण कर पा रही है, जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी।

नेक द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग न केवल किसी संस्था की सार्वजनिक छवि को प्रभावित करती है, बल्कि इसके माध्यम से सरकारी अनुदान, पाठ्यक्रम-स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता भी तय होती है। नेक के मूल्यांकन मापदंड बहुआयामी होते हैं, जिनमें किसी संस्था के मूल उद्देश्य, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अनुसंधान और नवाचार, बुनियादी ढांचा, छात्र सहयोग, शासन प्रणाली और 'बेस्ट प्रैक्टिस' को सम्मिलित किया जाता है। संस्थानों को ए++ से लेकर डी तक ग्रेड प्रदान किया जाता है। यह ग्रेड न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा का सूचक बनते हैं, बल्कि अनुदान प्राप्त करने, मान्यता बनाए रखने और छात्रों को आकर्षित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मगर विडंबना यह है कि ये ग्रेड कई बार संस्थान की जमीनी वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते।

ऐश 2020-21 रिपोर्ट, नेक वेबसाइट, और यूजीसी द्वारा प्रकाशित आंकड़े (2024 तक) को आधार बनाकर देखें तो, देश में कुल लगभग 45,000 कॉलेजों में से केवल 4,000 के आसपास ही ऐसे हैं जिन्होंने नेक से मान्यता प्राप्त की है। यह कुल संख्या का मुश्किल से 9 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार देश के 1,100 से अधिक विश्वविद्यालयों में से केवल 410 ही मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि नेक की पहुंच अभी भी सीमित है। इतना ही नहीं, जो संस्थान मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, वे भी कई बार इसे केवल एक औपचारिकता मानते हैं, न कि आंतरिक सुधार का अवसर।

वर्तमान प्रणाली में एक गंभीर समस्या यह देखी गई है कि मूल्यांकन के दौरान अक्सर संस्थानों द्वारा सजाए गए आंकड़ों, प्रस्तुतियों और तथाकथित 'बेस्ट प्रैक्टिस' को ही मूल्यांकन का आधार बना लिया जाता है। मूल्यांकनकर्ता संस्थानों द्वारा तैयार किए गए डॉक्युमेंटेशन पर भरोसा करते हैं, जिससे वास्तविक अकादमिक माहौल का सटीक चित्र सामने नहीं आ पाता। उदाहरणस्वरूप, कुछ संस्थानों को ए या ए+ ग्रेड दिया गया, जबकि छात्रों ने उसी अवधि में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, पुस्तकालयों में संसाधनों की अनुपलब्धता और फैकल्टी की अनुपस्थिति की शिकायतें दर्ज की थीं।

नेक के मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी को लेकर अकादमिक जगत में समय-समय पर प्रश्न उठते रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह संकेत मिला है कि कुछ संस्थान बाह्य प्रभावों और राजनीतिक संरक्षण के कारण ऊंचे ग्रेड प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान केवल संसाधनों की सीमितता के कारण कम ग्रेड प्राप्त करते हैं। इससे एक 'ग्रेड इनइक्विटी' उत्पन्न होती है, जो संस्थानों के बीच कृत्रिम प्रतिस्पर्धा और असमानता को जन्म देती है।

सवाल यह भी उठता है कि क्या ग्रेड में सुधार वास्तविक सुधार का प्रतिबिंब होता है या केवल पुनः मूल्यांकन और डॉक्युमेंटेशन की कलात्मक प्रस्तुति का परिणाम। 2022 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि 200 से अधिक संस्थानों ने अपनी ग्रेडिंग सुधारने हेतु पुनर्मूल्यांकन की याचिका दी थी, जिनमें से अधिकांश को अपेक्षाकृत बेहतर ग्रेड मिला। इससे यह धारणा बनती है कि मूल्यांकन प्रणाली में कठोरता और स्थायित्व का अभाव है।

नेक की प्रक्रिया में एक अन्य प्रमुख चिंता यह है कि यह डिजिटल शिक्षा, नवाचार और आधुनिक शिक्षण तकनीकों को अभी भी सीमित दृष्टि से देखती है। जब शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोक प्लेटफॉर्म, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग जैसे आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तब मूल्यांकन प्रणाली में इनकी भूमिका अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप, वे संस्थान जो डिजिटल रूपांतरण की दिशा में अग्रसर हैं, उन्हें भी पारंपरिक मापदंडों के आधार पर ही मूल्यांकित किया जाता है, जिससे उनका यथोचित मूल्यांकन नहीं हो पाता।

छात्रों की दृष्टि से देखा जाए तो नेक ग्रेडिंग कई बार भ्रम का कारण बनती है। विद्यार्थी उच्च ग्रेड देखकर किसी संस्थान में प्रवेश लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें अधूरी सुविधाएं, कमजोर फैकल्टी या खराब प्लेसमेंट की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। इससे न केवल छात्रों का समय और संसाधन व्यर्थ होते हैं, बल्कि संस्थान की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगते हैं। यदि ग्रेड गुणवत्ता के सटीक संकेतक नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर उनका क्या औचित्य रह जाता है?

निजी और ग्रामीण इलाकों के संस्थानों के बीच भी एक स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर होता है। शहरों में स्थित, संसाधन-सम्पन्न संस्थान अक्सर अच्छी ग्रेडिंग प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सीमित संसाधनों में काम कर रहे ग्रामीण कॉलेज, भले ही शैक्षणिक दृष्टि से बेहतर हों, अपेक्षित ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाते। इससे ना केवल शिक्षा की गुणवत्ता का असमान वितरण होता है, बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक विषमता को भी बल मिलता है।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं जैसे कि NAAC प्रक्रिया को स्वैच्छिक से अनिवार्य बनाने की दिशा में सोच, मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी प्लेटफॉर्म का समावेश, और डेटा स्वचालन की शुरुआत। परंतु ये पहल तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकतीं जब तक कि मूल्यांकनकर्ताओं की निष्पक्षता, संस्थानों की ईमानदारी और प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित न की जाए। कई बार मूल्यांकनकर्ता के अपने ही संस्थान की ग्रेडिंग का कम होना इस दिशा में और भी बड़े सवाल खड़ा करता है। इसके लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र, छात्र व फैकल्टी फीडबैक का सशक्तीकरण, और मूल्यांकन प्रक्रिया को दो-तरफा संवाद का मंच बनाना आवश्यक है।

नेक जैसी संस्था का होना उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक आवश्यकता है। यह गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करती है, परंतु इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इसकी अपनी प्रणाली में निरंतर आत्म-मूल्यांकन, आधुनिकीकरण और आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का स्वागत होना चाहिए। आज आवश्यकता है कि नेक स्वयं को केवल एक 'प्रत्यायन एजेंसी' के रूप में न देखकर 'गुणवत्ता सुधार के उत्प्रेरक' के रूप में स्थापित करे।

यदि शिक्षा व्यवस्था को समाज के लिए परिवर्तनकारी बनाना है, तो उसके मूल्यांकन की प्रणाली को भी उतना ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा। नेक को अपनी भूमिका पर पुनः चिंतन करते हुए उन मूल मूल्यों की ओर लौटना होगा, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी – अर्थात् सुधार की भावना, निष्पक्षता की प्रतिबद्धता, और गुणवत्ता की खोज।

नेक ग्रेडिंग व्यवस्था अपने प्रारंभिक उद्देश्य में सफल रही है, यह संस्थानों को जवाबदेही, पारदर्शिता और आत्म-चिंतन की दिशा में ले गई है। किंतु यह भी सत्य है कि आज यह व्यवस्था गुणवत्ता सुधार का माध्यम बनने की बजाय कई बार सूचकांक पूर्ति की होड़ बन गई है। हमें यह याद रखना चाहिए कि उच्च शिक्षा केवल इमारतों, लैब और प्रमाणपत्रों का खेल नहीं है। यह ज्ञान, मूल्य और समाज में बदलाव की प्रक्रिया है। यदि मूल्यांकन की प्रणाली उस मूल उद्देश्य से भटकती है, तो हम आंकड़ों की सुनामी में बहते हुए शिक्षा की आत्मा को खो देंगे।

हमें चाहिए एक ऐसा मूल्यांकन मॉडल जो संस्थान के साथ छात्र को भी केंद्र में रखे, जो संख्या से ज़्यादा अनुभव को मापे, और जो गुणवत्ता को सिर्फ रिपोर्ट नहीं, संस्कार बनाये।

मैं स्वयं ऐसे संस्थानों को निकट से जानता हूँ जहाँ शिक्षा की परिभाषा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। वहाँ संगीत, समाज, नृत्य, आधुनिकता और भारतीय ज्ञान परंपरा इन सभी को एक सजीव शैक्षणिक अनुभव के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कक्षाओं के भीतर और बाहर, छात्रों के सोचने, महसूस करने और समझने की क्षमता को गहराई से विकसित किया जाता है। यह संस्थान न केवल ज्ञान देता है, बल्कि छात्रों को अपने समाज, संस्कृति और अस्तित्व से जोड़ता है। अब सवाल यह उठता है – क्या एक ऐसी अन्य सैकड़ों संस्थाएं जो नई पीढ़ी को सोचने और सवाल उठाने की क्षमता से लैस कर रही हैं, महज इसलिए नकार दी जाएंगी क्योंकि वे नेक के औपचारिक ग्रेडिंग मापदंडों पर 'उत्कृष्ट' नहीं मानी जातीं?

यह प्रश्न न केवल उस एक संस्था पर लागू होता है, बल्कि उन सैकड़ों संस्थानों पर भी जो सीमित संसाधनों में भी एक बड़ी सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं होता; यह व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक चेतना का वाहक भी होता है। यदि मूल्यांकन प्रणाली इन मूल्यों को न माप सके, तो वह अधूरी ही कही जाएगी।

नेक जैसी संस्था का होना निःसंदेह आवश्यक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया को यथार्थ, विविधता और संवेदनशीलता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा को आंकने वाली कोई भी प्रणाली तब तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक वह उन संस्थानों की गहराई को न पहचान सके जो चुपचाप, बिना शोर-शराबे के, देश और समाज के भविष्य को आकार दे रहे हैं। यही वह बिंदु है जहाँ नेक को आत्मावलोकन करना होगा और यह तय करना होगा कि वह एक 'रेटिंग एजेंसी' बनना चाहती है या 'रचनात्मक शिक्षा की संरक्षक संस्था'।

नीतियों के बावजूद क्यों प्यासी है भारत की धरती?

जल संकट

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

भारत की धरती पर जल का संकट एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर हैरानी होती है कि इतनी योजनाओं, घोषणाओं और नीतियों के बावजूद यह देश बूंद–बूंद के लिए क्यों तरस रहा है। जब कोई देश दुनिया की 18 प्रति. जनसंख्या को समेटे हुए हो और उसके पास केवल 4 प्रति. ताजे जल संसाधन हों, तो संकट की आशंका तो बनती है, पर यदि यही देश दशकों से जल संरक्षण और जल प्रबंधन की योजनाओं का ढोल पीटता हो और फिर भी सूखा, प्यास, और जलजनित बीमारियाँ उसके हिस्से में आएं — तो यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं, यह नीति, प्रशासन और नागरिक चेतना की सामूहिक असफलता है।

भारत में पानी की स्थिति को अगर आंकड़ों की भाषा में समझें, तो भयावहता साफ़ दिखाई देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है — लगभग 25 प्रतिशत भूजल अकेले भारत निकालता है। 11 प्रति. से अधिक भूजल खंड 'अत्यधिक दोहित' यानी **over-e&ploited** की स्थिति में हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 21 प्रमुख शहरों के 2030 तक भूजल समाप्त होने की चेतावनी दी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर, 70 प्रति. जल स्रोत प्रदूषित हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और भारी धातुओं से दूषित यह जल 23 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। हर साल लगभग 2 लाख मौतें सिर्फ जलजनित बीमारियों से होती हैं — यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

पानी का यह संकट केवल ग्रामीण इलाकों या गरीबों तक सीमित नहीं है। 2019 में जब चेन्नई जैसे आधुनिक शहर को '□□□ □□□' का सामना करना पड़ा और जल ट्रेनें चलानी पड़ीं, तब यह साफ हो गया कि यह समस्या अब दरवाज़े पर नहीं, घर के भीतर आ चुकी है। और फिर भी हम इसे मौसमी समस्या मानकर हर बार भूल जाते हैं।

सवाल यह है कि नीतियाँ तो बनीं — राष्ट्रीय जल नीति (2012), जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान — पर फिर भी पानी का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? जवाब सरल है — हमारी नीतियाँ ज़मीन पर नहीं उतरतीं, और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता।

आज भी देश के अधिकांश किसान पानी की फिजूलखर्ची करने वाली फसलों की खेती करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे जल–संकटग्रस्त राज्य में धान और गन्ने की खेती केवल इसलिए होती है क्योंकि सरकार MSP और मुफ्त बिजली देती है। नतीजा — भूजल का तेज़ी से दोहन, खेतों का क्षरण, और जल स्रोतों का खत्म हो जाना। दूसरी ओर, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक जल संरक्षण उपायों की पहुंच केवल 9 प्रति. खेतों तक ही सीमित है। किसान जानते हैं, पर अपनाते नहीं — क्योंकि नीति और व्यवहार में दूरी है।

शहरों की बात करें तो पाइपलाइन से लेकर टंकी तक, हर जगह लीकेज और बर्बादी का आलम है। स्मार्ट मीटरिंग अभी भी अधिकांश नगरपालिकाओं के लिए नया शब्द है। पुनः उपयोग (रीसाइकिलिंग) और वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) जैसे उपाय कहीं–कहीं दिखते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अपनाए नहीं जाते।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जल संकट को अब भी केवल 'प्राकृतिक समस्या' समझा जाता है। जबकि यह एक स्पष्ट रूप से 'नीतिगत और नैतिक' संकट है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

अब समय आ गया है कि भारत पानी को 'मुफ्त संसाधन' मानना बंद करे और उसे 'जीवन मूल्य' की तरह देखे। इसके लिए कुछ गहन और ठोस सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, पानी की कीमत तय होनी चाहिए — चाहे वह पीने का हो, या सिंचाई का। मुफ्त पानी की संस्कृति ने उपभोग को बर्बादी में बदल दिया है। जल का मूल्य निर्धारण सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय विवेक के बीच संतुलन साध सकता है।

दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को केवल योजना पत्रों से निकालकर ज़मीनी हकीकत बनाना होगा। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सस्ती उपलब्धता, और स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र बनाना होगा। तीसरा, भूजल का प्रबंधन केवल सरकार का नहीं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों का भी कर्तव्य होना चाहिए। अटल भूजल योजना को इस दिशा में सफल मॉडल के रूप में बढ़ाया जा सकता है।

चौथा, किसानों को केवल फसल बीमा या सब्सिडी नहीं, जल आधारित फसल मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यह तभी होगा जब MSP का ढांचा जल संरक्षण के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देगा। देश को ऐसे नीतिगत हस्तक्षेपों की ज़रूरत है जो किसान की आय भी बढ़ाएं और पानी की बचत भी करें।

पाँचवां, शहरों में जल पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाए। जो नगर पालिकाएं wastewater recycle नहीं करतीं, उन्हें दंड और प्रोत्साहन दोनों के माध्यम से बदला जाए। बड़े भवनों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य हो, और इसके अनुपालन की निगरानी की जाए।

छठा, बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को केवल पर्यावरण अध्याय के रूप में न पढ़ाया जाए, बल्कि व्यवहार परिवर्तन के रूप में सिखाया जाए। यदि अगली पीढ़ी जल को 'कीमती' माने, तो आज की प्यास भविष्य की सूखी धरती को बचा सकती है।

सातवां, जल संरक्षण को 'जन आंदोलन' बनाना होगा — जैसा प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। लेकिन यह आह्वान केवल भाषणों में नहीं, बजट और प्रशासनिक प्रतिबद्धता में दिखना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय को केवल नल जोड़ने वाला मंत्रालय नहीं, जल नीति, जल शिक्षा और जल चेतना का नेतृत्व करना होगा।

साथ ही, निजी क्षेत्र की भूमिका को भी समझना और बढ़ाना होगा। जल एटीएम, पाइपलाइन प्रबंधन, स्मार्ट मीटरिंग, और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं में PPP मॉडल को बढ़ावा देकर न केवल निवेश लाया जा सकता है, बल्कि तकनीकी नवाचार भी हो सकते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण — हमें यह समझना होगा कि जल संकट केवल वैज्ञानिकों और नौकरशाहों का विषय नहीं है। यह आम नागरिक का संकट है। हर घर, हर हाथ को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि पानी को बर्बाद नहीं किया जाएगा, और हर बूंद का सम्मान होगा।

जलवायु परिवर्तन के इस युग में, जब बारिश की मात्रा अनिश्चित हो गई है, और हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं — हमें जल को 'अनंत' नहीं, बल्कि 'सीमित और नाजुक' संसाधन मानना होगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में जल को देवता का दर्जा मिला है — लेकिन विडंबना यह है कि आज वही जल नदियों में मल–मूत्र के रूप में बह रहा है, या गंदे नालों से होकर भूजल में जहर घोल रहा है। इसलिए आज का भारत केवल 'जल संकट' नहीं झेल रहा, बल्कि वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जल संकट में डूबा भारत, विकास के हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता जाएगा — चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि, उद्योग या सामाजिक समरसता। अंततः यही कहा जा सकता है कि जल संकट केवल पानी की समस्या नहीं है — यह व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और नीयत की भी परीक्षा है। यदि हमने अब भी नहीं संभला, तो इतिहास गवाह रहेगा कि हमने एक ऐसे संसाधन को खो दिया, जो जीवन का मूल था, और जिसकी एक–एक बूंद सोने से भी महंगी थी। अब वक्त आ गया है — नीतियों की बौछार से बाहर निकलकर बूंद–बूंद बचाने के व्यवहारिक आंदोलन को अपनाने का। क्योंकि आने वाले वर्षों में 'जल' ही 'राजनीति', 'आर्थिक ताकत' और 'सामाजिक न्याय' का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस पर विशेष

भयानक तबाही मचा सकते हैं कुछ क्षुद्रग्रह

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

प्रतिवर्ष 30 जून को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास वर्ष 1908 में हुई क्षुद्रग्रह (एस्टेरायड) घटना की वर्षगांठ के प्रतीक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 2016 में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी दिन साइबेरिया और उसके आसपास हुए तुंगुस्का क्षुद्रग्रह के प्रभाव को समझने के लिए ही इस तिथि का चयन किया गया था। इस दिन को चिह्नित करने का विचार एसोसिएशन ऑफ स्पेस एक्सप्लोरर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति द्वारा समर्थन दिया गया था। दरअसल 30 जून 1908 को तुंगुस्का नदी के करीब एक बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्का प्रभाव कहा गया। उस विस्फोट में कई किलोमीटर क्षेत्र में जमीन तहस-नहस हो गई थी। क्षुद्रग्रह के चलते पृथ्वी पर हुआ वह नुकसान अभी तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। यह दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को उस संकट के बारे में जागरूक करना है, जो क्षुद्रग्रह के प्रभाव से ब्रह्मांड पर हो सकता है। इस दिवस के माध्यम से क्षुद्रग्रह के प्रभाव के चलते होने वाले खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन छेड़ा गया है।

क्षुद्रग्रह दिवस का लक्ष्य क्षुद्रग्रहों और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देने के अलावा सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को हमारे ग्रह को भविष्य के क्षुद्रग्रह प्रभावों से बचाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जून को क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में घोषित करने के लिए लाए गए संकल्प में तय किया था कि दुनियाभर में लोगों को क्षुद्रग्रहों के घातक प्रभावों के बारे में जागरुक किया जाएगा। दरअसल आज भी विश्व में अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि आखिर ये क्षुद्रग्रह हैं क्या और किसी क्षुद्रग्रह की घटना पृथ्वी पर कितना विनाश कर सकती है? हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में क्षुद्रग्रहों की क्या भूमिका है, भविष्य में उनके संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, क्षुद्रग्रह भविष्य की खोज के लिए कैसे मार्ग प्रदान करते हैं और हम अपने ग्रह को क्षुद्रग्रहों के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं, यह दिवस इन्हीं सब बातों को जानने-समझने तथा किसी क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने पर होने वाले विनाशकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 1908 के तुंगुस्का प्रभाव की वर्षगांठ का प्रतीक है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में पॉडकामेनेया तुंगुस्का नदी के ऊपर आसमान में एक बड़ा विस्फोट हुआ था। नासा के अनुसार अनुमान लगाया गया था कि उस क्षुद्रग्रह ने करीब 33500 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था। 220 मिलियन पाउंड की उस अंतरिक्ष चट्टान ने अपने आसपास की हवा को 44500 डिग्री फॉरेनहाइट तक गर्म कर दिया था। करीब 28 हजार फीट की ऊंचाई पर दबाव और गर्मी के संयोजन ने क्षुद्रग्रह के टुकड़े को नष्ट कर दिया था, जिससे आग का गोला पैदा हुआ और उससे करीब 185 हिरोशिमा बमों के बराबर ऊर्जा निकली। उस भयंकर विस्फोट से पैदा गई आग ने जंगल के करीब 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 80 मिलियन से भी ज्यादा पेड़ों को जलाकर राख कर दिया था। माना गया था कि उस विस्फोट के लिए कोई क्षुद्रग्रह या धूमकेतु जिम्मेदार था। क्षुद्रग्रह दिवस की स्थापना 2013 के चेल्याबिंस्क उल्का विस्फोट के अगले वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने खगोलशास्त्री और क्रीन के प्रमुख गिटारवादक डा. ब्रायन मे, बी612 फाउंडेशन के अध्यक्ष डेनिका रेमी, अपोलो 9 अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वेकार्ट और फिल्म निर्माता ग्रिग रिक्टर्स के साथ मिलकर जागरूकता को बढ़ावा देने और लोगों को हमारे ब्रह्मांड के निर्माण में क्षुद्रग्रहों के महत्व तथा हमारे सौरमंडल में उनकी भूमिका के बारे में ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। बी612 नामक संगठन एक ऐसा संगठन है, जो पृथ्वी को क्षुद्रग्रह प्रभावों से बचाने और ग्रह रक्षा के मुद्दों पर विश्वभर में निर्णय लेने की जानकारी देने और अग्रेषित करने की दिशा में कार्य करता है।

क्षुद्रग्रह छोटे आकाशीय चट्टान रूपी पिंड होते हैं, जो सदैव सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये वो पिंड हैं, जो किसी कारण से ग्रह नहीं बन पाए। क्षुद्र ग्रह को ग्रहिका भी कहते है। ये आकाशीय पिंड किसी ग्रह से छोटे होते हैं लेकिन ग्रहों की ही भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दरअसल तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, इन्हीं पिंडों को क्षुद्रग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष विज्ञानियों के मुताबिक क्षुद्र ग्रह एक ग्रह के हिस्से हैं, जो हजारों साल पहले टूटे थे। क्षुद्रग्रह चट्टानी-धात्विक वस्तुएं हैं, जिनका आकार एक छोटे से कंकड़ के आकार से लेकर 600 मील तक भी होता है। इन्हें सौरमंडल का बचा हुआ पदार्थ भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में कई लाख क्षुद्रग्रह मौजूद हैं और कई की खोज अभी बाकी है। कुछ क्षुद्रग्रह तो इतने छोटे होते हैं कि उनका पता लगाना मुश्किल होता है। ज्यादातर क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं लेकिन कुछ की कक्षाएं अधिक विलक्षण होती हैं।

करीब 10 लाख ज्ञात क्षुद्रग्रहों में से सबसे बड़ी संख्या मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में सूर्य से करीब 2 से 4 खगोलीय इकाई दूर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसका व्यास करीब 1083 किलोमीटर है, जिसकी खोज 1801 में हुई थी। दरअसल उस दौरान तारों का नक्शा बनाते समय इटली के खगोल शास्त्री ग्यूसेप पियाजी ने गलती से मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक हजार किलोमीटर (करीब 600 मील) व्यास की एक वस्तु की खोज की थी। उन्होंने उस वस्तु का नाम अनाज और फसल की रोमन देवी के नाम पर 'सेरेस' रखा, जो खोजा जाने वाला पहला क्षुद्रग्रह था। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रहों के पट्टे में रहता है। प्लूटो क्षुद्रग्रह सेरेस से करीब ढ़ाई गुना बड़ा है।

अंतरिक्ष विज्ञानियों का मानना है कि सेरेस शुष्क और धूसर दिखाई दे सकता है लेकिन संभवत: इसके अतीत में एक तरल महासागर था। ज्यादातर क्षुद्रग्रह पृथ्वी और उस पर पनप रहे जीवन के लिए खतरा नहीं हैं लेकिन कुछ क्षुद्रग्रह इतने खतरनाक हैं और अगर वे पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो भयानक तबाही मचा सकते हैं।

साप्ताहिक बाजार में कम नहीं दुकानदारी, तापमान में आई कमी

बैतूल। रविवार सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर रुक-रुककर दिनभर चलता रहा। इससे तापमान कम हुआ है और मौसम ठंडा होने से सभी को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते चौबीस घंटे यानि 28 जून से 29 जून सुबह 8 बजे तक जिले में महज 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जबकि अभी तक 126.7 मिमी बारिश हो चुकी हैं। हालांकि पिछले साल से इस बारिश साल की बारिश का आंकड़ा बढ़ा है। पिछले साल 29 जून तक जिले में 124.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। जिले में अभी तक तेज बारिश का दौर शुरू नहीं हो सका है। रूक-रूककर बारिश हो रही हैं। जिससे बारिश का आंकड़ा तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि रविवार को बैतूल में दिन भर रूक-रूककर कभी तेज तो कहीं रिमझिम बारिश होते रही। बताया गया कि जिले में वर्षाकाल के दौरान अभी तक सर्वाधिक बारिश शाहपुर ब्लाक में हुई है। यहां अब तक 171.0 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, वहीं दूसरे नंबर पर प्रभातपट्टन में 169.8 मिमी और सबसे कम बारिश बैतूल में 52.0 मिमी दर्ज की है। इसके अलावा अन्य ब्लॉकों में बारिश का आंकड़ा 100 मिमी से ऊपर है।

जिले में 82 फीसदी बुआई का काम पूरा- अच्छी बारिश से किसानों ने बोवनी का काम तेज कर दिया है। कई किसान 8 जून के बाद बुआई चालू कर दी थी, ऐसे में इन किसानों की फसल करीब 18 से 20 दिनों की हो चुकी है। बीज अंकुरित होकर खेत लहलहाने लगे है। वही जिन किसानों ने बुआई नहीं की थी, वह किसान भी बुवाई में जुट गये है। शनिवार को मौसम खुले रहने से अधिकांश किसानों ने बुआई का काम निपटा लिया है। वैसे जिले में जिले में 16 जून से मानसून एक्टिव हुआ है। जिसके बाद किसानों ने बुआई कार्य शुरू कर दिया था। किसानों के अनुसान रिमझिम बारिश फसलों के लिए फायदेमंद बताई जाती है। कृषि विभाग के अनुसार इस साल जिले में 4 लाख 43 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसल की बुआई का रकबा तय किया है।

अधिकतम तापमान 28 डिग्री किया दर्ज- जिले में हो रही लगातार बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। रविवार जिले का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री था। बारिश के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने से सभी को उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की मानें तो अगले दो दिन बारिश होने की संभावना है। इससे जून में बारिश का सूखा पूरा हो जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो-तीन दिन बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार मानसून की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई है। आने वाले दिनों में मानसून की गति बढने की संभावना है।

साप्ताहिक बाजार पर पड़ा असर- रविवार सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। जिसका असर साप्ताहिक बाजार पर देखा गया। बारिश के साप्ताहिक बाजार में दुकानदार और ग्राहक कम नजर आये। कोठी बाजार के साप्ताहिक बाजार में दोपहर 12 बजे तक बहुत कम दुकानें लगी हुई थी। वहीं ग्राहक भी कम थे। जिले के आसपास क्षेत्र से सब्जियां कम आने से सब्जियों के दाम भी बढ़ गये। रविवार साप्ताहिक बाजार में टमाटर 40 रूपये किलो तक बिके। इसके अलावा आलू 30 रूपये प्रति किलो थी। अन्य सब्जियों के दाम भी 15 से 20 रूपये किलो तक रहे। बारिश के कारण बाजार में दुकानदार तिरपाल लगाकर दुकाने संचालित करते देखे गये।

सतपुड़ा डैम के खुले तीन गेट

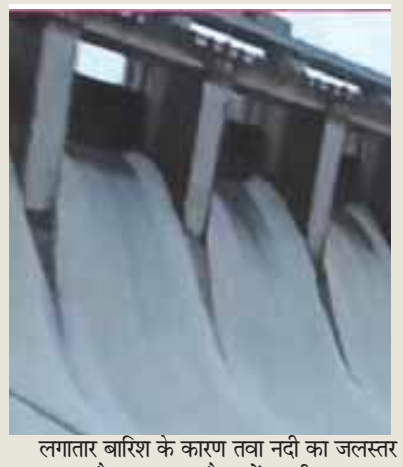

लगातार बारिश के कारण तवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतपुड़ा डैम में पानी का स्तर 1429.50 फीट तक पहुंचने पर तीन गेट खोलने पड़े। रविवार सुबह तक एक ही गेट खुला था, लेकिन बाद में तीन गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। इससे तवा नदी के निचले इलाकों में जलस्तर में वृद्धि हुई है। घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में अब तक 158 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिससे जल स्रोतों और बांधों के भरने की उम्मीद बढ़ गई है।

जिले के ब्लाकों में अब तक दर्ज बारिश

ब्लाक	बारिश (मिमी में)
बैतूल	52.0
घोड़ाडोंगरी	158.0
चिचोली	139.2
शाहपुर	171.0
मुलताई	115.1
पट्टन	169.8
आमला	118.0
भैंसदेही	106.0
आठनेर	109.6
भीमपुर	132.0
कुल	126.7

ब्रम्हांड से जोड़ दिया बैतूल का इतिहास सराहनीय : हेमन्त खण्डेलवाल

मैं बैतूल हूँ कि मंच पर दी गई जीवंत प्रस्तुति, राजा जैतपाल, तात्याटोपे, से लेकर राजा ईल की कहानी से रूबरू हुए दर्शक

बैतूल। जिले के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले के इतिहास की परिकल्पना युवाओं के सहयोग से मंच पर नजर आई। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा मैं बैतूल हूं... का मंचन बैतूल के उत्कृष्ट कलाकारों ने जीवंत कर दिखाया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि बैतूल विधायक एवं कार्यक्रम के संरक्षक हेमन्त खण्डेलवाल, नपा अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार समेत बडी संख्या में दर्शक गण शामिल हुए। इस अवसर पर युवा वर्ग द्वारा किये गए इस प्रयास की विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने खुलकर सराहना कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि, मैं बैतूल हूं के शीर्षक को कलाकारों ने जीवंत कर दिखाया। जिस तरह ब्रम्हांड से बैतूल का इतिहास जोड़ा गया, यह प्रयास काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि यह तो एक छोटा सा प्रयास है। कोशिश की जाए तो यह कार्यक्रम बडे रूप में आयोजित किया जा सकता है। जिसमें हजारों की संख्या में जिलेवासी शामिल होकर जिले के इतिहास से रूबरू हो सकते हैं।

राजा जैतपाल से लेकर राजा ईल और स्वतंत्रता सैनानी मंच पर आए नजर

दरअसल मैं बैतूल हूं .. के मंचन की पटकथा और मंचन उत्कृष्ट कलाकार शिरीष ध्वनि और सूर्यदीप त्रिवेदी द्वारा तैयार की गई थी। ग्रुप में शामिल कलाकारों ने राजा जैतपाल से लेकर खण्डारा रियासत के राजा ईल, तात्या टोपे का अभिनय साकार किया। खास बात ये है कि,नाटक के मंचन में अंग्रेजों का शाषन काल तक शामिल किया गया था। अंग्रेजो ने जिस तरह जिले में अपनी आमद दी और देश को आजादी दिलाने में जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका क्या रही इसे कलाकारों ने अपने अभिनय के रूप में जब प्रस्तुत किया तो हॉल तालियों की गडगडाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्यों की बेहतरीन झलक भी नजर आई। आदिवासी समुदाय के युवाओ ने कोरकू और गोंधळ नृत्य की प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी, विधायक हेमन्त खण्डेलवाल ने सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका उत्साह वर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार आदर्श सोनकपुरिया एवं संकल्प सिंह चौहान ने अतिथियों समेत सभी दर्शकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सताक्षी गौर द्वारा किया गया।

कुनबी समाज के विकास के लिए हर स्तर पर करेंगे सहयोग : हेमंत खंडेलवाल

शिवाजी परिसर गौठाना में मंगल भवन निर्माण का हुआ शुभारंभ

बैतूल। क्षत्रिय लोनारी कुनबी समाज सेवा संगठन जिला बैतूल द्वारा शिवाजी परिसर गौठाना में रविवार 29 जून को मंगल भवन निर्माण हेतु भूमिपूजन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डी.डी. उइके रहे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, नगर पालिका परिषद बैतूल की अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, समाजसेवी डॉ. एन.आर. मानकर, वसंत वागद्रे, दिनेश माथनकर, संगठन के जिलाध्यक्ष यशवंत (मुन्ना) मानकर सहित समस्त जिला कार्यकारिणी उपस्थित रही। मंगल भवन के लिए क्रय की गई भूमि में सहयोग देने वाले प्रमुख समाजसेवियों का संगठन द्वारा पुष्पमालाओं और श्रीफल से सम्मान किया गया। इनमें डॉ. एन.आर. मानकर, वसंत वागद्रे, दिनेश माथनकर, पंकज साबले और जिलाध्यक्ष यशवंत मुन्ना मानकर का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा। इस भूमि की क्रय प्रक्रिया संगठन के पूर्व अध्यक्ष मनोज धोटे के नेतृत्व में पूरी की गई थी, जिनका भी मंच पर अभिनंदन किया गया। विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रिय लोनारी कुनबी समाज एक संगठित और प्रेरणादायक समाज है, जो लगातार सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि समाज द्वारा मंगल भवन का निर्माण किया जाना एक दूरदर्शी पहल है, जो आने वाली पीढ़ियों को एकजुटता, सहयोग और सुसंस्कारों का संदेश देगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि समाज के विकास के लिए वे हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि मंगल भवन सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन का केंद्र बनेगा, यह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शन स्थल की भूमिका निभाएगा। विधायक ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए समाजजनों से आग्रह किया कि वे एकजुट होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में आगे आएं। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के चुनाव में सफलता प्राप्त करने वाले रोशन मागरदे और गौरव मागरदे को संगठन द्वारा प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के उपरांत संगठन की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले भर में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, ताकि समाज को और अधिक संगठित व प्रभावशाली बनाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन संयोजक डॉ. उज्ज्वल पांसे एवं मनोज धोटे ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. उज्ज्वल पांसे, मीडिया प्रभारी पंकज धोटे, हरीश चढोकार, राजेश बारस्कर एवं संगठन की समस्त कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे।

यूपी में कथा वाचक के साथ अमानवीय घटना के विरोध में यादव समाज ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। इटावा जिले के बकेबर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादरपुर में विगत 22 जून को श्रीमद्भागवत कथा वाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथियों के साथ हुई अमानवीय, जातिगत और बर्बर घटना से आक्रोशित यादव समाज ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। घटना के विरोध में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा मध्यप्रदेश के बैनर तले समस्त यादव समाज के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्र भारत में जातिवाद की संकीर्ण सोच अब भी समाज के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रही है। दादरपुर में कथा वाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों के साथ सरेआम मारपीट की गई, जबरन बाल काटे गए, मुंडन कर नाक रगड़वाया गया। यादव समाज का कहना है कि इस कृत्य का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना शर्मनाक है। संतोष यादव ने कहा कि इस घटना से पूरे देश का यादव समाज आहत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई जातिगत जहर घोलने की हिम्मत न कर सके। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने मांग की कि इस कांड को सामूहिक सामाजिक अपराध माना जाए और दोषियों पर राष्ट्रीय एकता भंग करने, जातीय विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और एकजुटता का प्रदर्शन किया। समाजजनों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से इस मामले को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने की मांग की। यादव समाज ने चेताया कि यदि समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष संतोष यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने इस जातिगत हमले की घोर निंदा करते हुए सरकार से न्याय की मांग की।

भौरा बायपास पर ब्रिज के पास मिट्टी का कटाव बना खतरा

नेशनल हाईवे की रोड पर कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना

बैतूल/भौरा। भौरा से होकर निकली नेशनल हाईवे-46 की बायपास रोड पर खतरा गहराता जा रहा है। लगभग 20 फीट गहराई में बनाई गई इस रोड के साइड की जमीन पर तेज कटाव हो रहा है, जो सीधे हाईवे पर मिट्टी गिरने का कारण बन रहा है। खासकर भौरा-बीजादेही मार्ग पर बने ब्रिज के पास की जमीन पर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। यदि समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यह मार्ग नेशनल हाईवे का हिस्सा होने के कारण यहां वाहनों की रफ्तार आमतौर पर तेज रहती है। यदि ऊपर से मिट्टी का कटाव अचानक हाईवे पर गिरा, तो वाहन फिसलने या टकराने जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यह खतरा खासतौर पर बारिश के समय कई गुना बढ़ सकता है। जानकारी के अनुसार भौरा बायपास निर्माण के दौरान एनएचएआई ने रोड बनाने के लिए लगभग 20 फीट गहराई तक खुदाई की थी। इसके बाद साइड की जमीन को स्थिर करने के लिए कोई स्थायी संरचना या रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई गई, जिससे अब यह जमीन कटाव की चपेट में है। मिट्टी का यह कटाव लगातार नीचे बनी रोड पर गिर रहा है। भौरा-बीजादेही रोड पर बने ब्रिज के साइड में स्थित शराब दुकान के पास की जमीन में कटाव सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। बाईपास हाईवे पर स्थित शराब दुकान के बगल वाली भूमि के भू-स्वामी मोहन मालवीय ने बताया कि वे कई बार इस समस्या को लेकर एनएचएआई अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बारिश के समय मिट्टी तेजी से धंसती है। यदि ऊपर से मिट्टी रोड पर अचानक गिरी, तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

एनएचएआई की चुप्पी पर उठे सवाल

स्थानीयों ने सवाल उठाया है कि बार-बार शिकायत के बावजूद भी एनएचएआई ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही अधिकारियों की नींद खुलेगी? भौरा बायपास पर मिट्टी का यह कटाव अब महज भू-क्षरण नहीं, बल्कि जानलेवा खतरा बन सकता है। हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के लिए यह एक अनदेखा खतरा है, जो किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। समय रहते कदम उठाना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गया है।

इनका कहना है-

आप जगह की फोटो भेजिए, मैं आज ही अधिकारियों को भेजकर निरीक्षण कराता हूं। यदि यह स्थान मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, तो आवश्यक कार्यवाही तत्काल शुरू की जाएगी। सडक़ की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

- मनीष कुमार मीणा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

भोपाल, ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश

11 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। रविवार को भोपाल, नर्मदापुरम, रतलाम, धार और रायसेन, विदिशा और खंडवा में में सुबह से रुक-रुककर तेज और रिमझिम बारिश जारी थी।

मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे के दौरान साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। 1 जुलाई से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनेगा। इससे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश होगी।

भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाले ब्रिज को लेकर एक्शन

सीएम ने 8 अफसरों को किया सस्पेंड, डिजाइन और निर्माण एजेंसी भी ब्लैकलिस्ट

भोपाल (नप्र)। भोपाल के 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग आरओबी के निर्माण में हुई गंभीर लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 8 अफसरों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं।

शनिवार रात मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि मैंने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दो सीई सहित सात इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। एक सेवानिवृत एसई के खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी।

इस प्रोजेक्ट में आरओबी का त्रुटिपूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने पर निर्माण एजेंसी एवं डिजाइन कंसल्टेंट, दोनों को ब्लैक लिस्ट किया है। आरओबी में आवश्यक सुधार के लिए कमेटी बनाई गई है। सुधार के बाद ही आरओबी का लोकार्पण किया जाएगा।

सस्पेंड अफसरों पर आज तय होंगे आरोप- अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई ने बताया कि जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ कल आरोप तय किए जाएंगे।

समय-सीमा से एक साल प्रोजेक्ट लेट- ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 21 मई 2022 को शुरू था। समय-सीमा से प्रोजेक्ट एक साल देरी से चल रहा है। 17 करोड़ 37 लाख की लागत वाले ब्रिज का निर्माण अगस्त 2024 में पूरा होना था। लेकिन, जून 2025 में भी इसे बनाने की प्रक्रिया जारी है।

मंत्री राकेश सिंह ने कराई थी जांच- बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) से जांच करवाई थी। एनएचएआई ने ब्रिज को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 35-40 किमी प्रति घंटा से अधिक गति से गाड़ी नहीं चलाने का सुझाव दिया गया है। इससे अधिक स्पीड में गाड़ी चली तो हादसा होने का खतरा है। ऐसे में इस ब्रिज को रिडिजाइन करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

सोशल मीडिया पर मीम्स भी बने

भोपाल में बने इस रेलवे ओवरब्रिज को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाए हैं। इस ब्रिज पर 90 डिग्री के एंगल से मोड़ दिया गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहां वाहन कैसे टर्न लेंगे। वाहनों के या तो ब्रिज की दीवारों से या फिर आपस में टकराने का खतरा बना रहेगा।

क्रॉसिंग बंद होने से ब्रिज की जरूरत

ब्रिज के निर्माण के समय रेलवे ने भी 90 डिग्री की इस टर्निंग पर आपत्ति की थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने यहां जगह कम होने का हवाला देते हुए कहा था कि और कोई विकल्प नहीं है। ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बाद इस इलाके के लिए आरओबी एक बड़ी जरूरत है। इसलिए कम जगह में भी इसे बनाना होगा।

18 महीने में बनकर तैयार होना था

इस ब्रिज का निर्माण मई 2022 में शुरू हुआ था और इसे 18 महीने में पूरा करना था, लेकिन अब तक पूरी तरह से नहीं बन सका है। इसकी लागत 18 करोड़ रुपए है। 648 मीटर लंबे और 8 मीटर की चौड़ाई वाले ब्रिज का 70 मीटर हिस्सा रेलवे का है।

प्रदेश की औद्योगिक विकास दर को गति देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

औद्योगिक समूहों से जुड़ाव, प्रदेश में निवेश को सुगम बनाने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए सूरत में हो रहा है इंटरएक्टिव सेशन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की कृषि विकास दर के समान औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने के लिए के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। इसी उद्देश्य से उद्योग व्यापार और निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर समिट आयोजित करने और देश-विदेश के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक केंद्रों से संपर्क का क्रम जारी है। राज्य सरकार की इस पहल का प्रदेश को लाभ भी मिल रहा है। इसी क्रम में आज सूरत में 'मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरएक्टिव सेशन' रखा गया है। यह आयोजन उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 अभियान की श्रृंखला में बेंगलुरु के बाद दूसरा बड़ा संवाद है। क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक समूह से जुड़ाव बढ़ाना और प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना तथा निवेश को सुगम बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। सूरत देश का प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। वहां के उद्योग व्यापार जगत के सहयोग से प्रदेश में निवेश गतिविधियों को प्रोत्साहन मिले, इस उद्देश्य से वहां समिट आयोजित किया गया है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सूरत प्रस्थान से पहले मीडिया के लिए जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किऐ।

भोपाल में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के पोस्टर, बताया हीरो

डेरे के इमाम बोले- ये सेलिब्रेशन नहीं, एक वैचारिक प्रदर्शन है

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-6 के पास स्थित ईरानी डेरा में इस बार मोहर्रम के मौके पर ईरान के नेताओं के पोस्टर लगाए गए हैं। कई जगहों पर शिया समुदाय के प्रभावशाली धार्मिक और सैन्य नेताओं आयतुल्ला अली खामेनेई, अली अल सिस्तानी, जनरल मोहम्मद बाघेरी, कासिम सुलेमानी और अयातुल्ला खोमैनी के बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। एक जगह आयतुल्ला अली खामेनेई का फोटो तिरंगे के नीचे लगा है।

फतेहपुर से भोपाल आए ईरानी डेरे के इमाम शाहकार हुसैन ने कहा कि हर साल पोस्टर्स लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा है। इसकी वजह है 12 दिन की वह जंग, जिसे इजराइल ने बुजदिलाना अंदाज में शुरू किया और ईरान ने करारा जवाब दिया।

इजराइल-ईरान के बीच संघर्ष विराम को लेकर उन्होंने कहा कि सीजफायर की मांग खुद इजराइल-अमेरिका ने की। यह सिर्फ ईरान नहीं, इंसाफ पसंद तमाम लोगों की जीत है।

खामेनेई सिर्फ धर्मगुरु नहीं, अब आलमी लीडर बन चुके हैं- ईरानी डेरे के इमाम शाहकार हुसैन के मुताबिक, आयतुल्ला खामेनेई ने खुद कहा है कि यह जीत मोहर्रम की देन है। हमने इमाम हुसैन से सीखा है कि जुल्म के खिलाफ सिर नहीं झुकाते। मोहर्रम का यही

संदेश है और इस बार इसे दुनिया के सामने रखना जरूरी था कि हक की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं।

शाहकार हुसैन ने कहा- यहां जो बैनर लगे हैं, वे कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रदर्शन हैं। यह दिखाने के लिए है कि अगर इमाम हुसैन की राह पर चला जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है।

भारत के रुख की तारीफ, ईरानी कल्चरल हाउस ने भेजा शुक्रिया पत्र- शाहकार हुसैन ने कहा कि इसमें भारत का बैलेंस रवैया रहा है। ईरानी कल्चरल हाउस ने एक लेटर जारी किया है। भारत की अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि वह साथ में खड़े रहे, भारत का रवैया बिल्कुल सही था, जंग में किसी का फायदा नहीं है, नुकसान ही है। उन्होंने जंग रुकवाने की कोशिश भी की, मगर यूरोपियन कंट्रीज का स्टैंड गलत था।

अहमदाबाद में खुलेगा मप्र औद्योगिक विकास निगम का ऑफिस : मुख्यमंत्री

सूरत में सीएम बोले- बिना गुजरात की भूमिका के भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं

भोपाल (नप्र)। मप्र सरकार औद्योगिक और रोजगार के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। सीएम डॉ मोहन यादव ने आज गुजरात के सूरज में उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट को संबोधित किया।

सीएम ने अपने संबोधन में कहा- मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का कार्यालय अब अहमदाबाद में भी खोला जाएगा। इससे गुजरात के उद्यमियों को हमारे राज्य में निवेश करने में और अधिक सुविधा होगी।सीएम ने कहा- गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच औद्योगिक विकास निगम का नया कार्यालय औद्योगिक सेतु केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा- गुजरात की धरती पर आकर मैं आत्मविभोर हूं। यह केवल 300 वर्षों का इतिहास नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी हुई सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर का गौरवशाली प्रतीक है। सीएम ने कहा- भगवान श्रीकृष्ण ने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की और द्वारका बसाकर एक आदर्श राज्य का निर्माण किया। वास्तव में, बिना गुजरात की भूमिका के भारत का पूर्ण उत्थान संभव नहीं।

कठिन परिस्थितियों में भी गुजरात के लोग साधारण जीवन जीते हैं- सीएम ने कहा- गुजरात ने न केवल अध्यात्म का, बल्कि उद्योग, व्यापार और सादगीपूर्ण जीवनशैली का भी मार्ग प्रशस्त किया है। यहां के लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधारण और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। यही गुजरात की विशेषता है, जो हमारी सनातन संस्कृति की सच्ची पहचान है।

महात्मा गांधी हों या सरदार वल्लभभाई पटेल इन महान व्यक्तित्वों ने भारत को दिशा दी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत को स्वतंत्रता दिलाई, वहीं पटेल जी ने 600 से अधिक रियासतों को एकत्र कर भारत को अखंड राष्ट्र बनाया।

आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। साल 1947 में जहां हम 15वें स्थान पर थे, आज हम विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं।इसका श्रेय निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता को जाता है।

गुजरात ने व्यापार के मामले में देश में उदाहरण पेश किया- सीएम ने कहा- गुजरात में व्यापार करने की सरलता, व्यवस्था की पारदर्शिता और नवाचार के प्रति जागरूकता ने पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज यदि कोई भारत के औद्योगिक विकास को देखना चाहता है, तो उसे गुजरात अवश्य आना चाहिए।

जबलपुर में पत्नी-बेटे के साथ जॉय स्कूल संचालक गिरफ्तार

सेना में अधिकारी रही बहू ने लगाया धर्मांतरण का आरोप, कहा- प्रताड़ित कर घर से निकाला

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अखिलेश मेबिन, उनकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है।

सेना में अधिकारी रह चुकी अखिलेश की 36 वर्षीय बहू आकांक्षा अरोरा ने 28 जून को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उस जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर ससुर, सास और पति ने उससे मारपीट की है। नर्मदा रोड आदर्श नगर निवासी अपनी शिकायत में आकांक्षा ने बताया कि पति तनय मेबिन स्कूल का डायरेक्टर है। 20 दिसंबर 2017 में उसका विवाह तनय से हुआ था। वह सेना में कैप्टन के पद रह चुकी है। शादी के कुछ माह तो सब कुछ ठीक रहा पर उसके बाद से ससुराल वालों का आचरण बदल गया। मारपीट करने के साथ-साथ अखिलेश मेबिन उनकी पत्नी और बेटा ईसाई बनने का कह रहे हैं।

इससे पहले भी छात्रों के परिजनों से करोड़ों रुपए की अधिक फीस वसूली और भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में अखिलेश जेल जा चुके हैं।

रीवा में खड़े ट्रक से टकराई बाइक, तीन की मौत

मृतक किशोरी की पहचान नहीं हो सकी ; दूसरी 8 वर्षीय बच्ची की हालत गंभीर

रीवा (नप्र)। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई।

जानकारी के मुताबिक, कटरा से गढ़ की ओर जा रहे बाइक सवार सूरज गिरी (24) और रावेंद्र साकेत (46) की मौके पर ही मौत हो गई। इनके साथ बाइक पर सवार एक 8 वर्षीय बच्ची भी थी, जिसे गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है।

अभी एक बच्ची की पहचान नहीं- थाना प्रभारी अवनीश पांडेय ने बताया कि हादसा कलवारी मोड़ से 100 मीटर दूर हुआ। मृतकों में एक बच्ची भी शामिल है, जिसकी पहचान की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है।

पुलिस जांच में जुटी- स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और बाइक नंबर के आधार पर पहचान की कार्रवाई शुरू की। शवों का पोस्टमॉर्टम परिजनों की मौजूदगी में कराया जाएगा। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रक किन नियमों के तहत सड़क किनारे खड़ा था।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे या अमित अग्रवाल, या फिर मनोज पिंगुआ के सिर सेहरा बंधेगा? यह सस्पेंस बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन 30 जून को रिटायर हो जाएंगे। श्री जैन की विदाई और नए मुख्य सचिव के परिचय /स्वागत के लिए 30 जून को पूर्वान्ह 11 बजे साय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इससे साफ़ हो गया कि राज्य को 30 जून को नया चीफ सेक्रेटरी मिल जाएगा। मध्यप्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के अनुभव के आधार पर लग रहा है चीफ सेक्रेटरी के बारे में निर्णय दिल्ली से होगा। तीनों दावेदारों में सुब्रत साहू वरिष्ठ हैं। वे 1992 बैच के आईएएस हैं। सुब्रत साहू कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री के एसीएस थे। कांग्रेस राज में मुख्यमंत्री सचिवालय में रहे कुछ के जेल जाने और कुछ के विवादों में रहने के बाद भी सुब्रत साहू पाक-साफ़ रहे। इस कारण वे मुख्य सचिव की दौड़ में हैं। 1993 बैच के अमित अग्रवाल दिल्ली में पदस्थ हैं। अब वे दिल्ली छोड़कर रायपुर आते हैं या नहीं, यह बड़ा सवाल है। मुख्य सचिव की रेस में 1994 बैच के आईएएस और एसीएस गृह मनोज पिंगुआ भी हैं। मनोज पिंगुआ को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पसंद बताया जा रहा है। कहा जा रहा कि इन तीन आईएएस में से कोई एक मुख्य सचिव बनेगा और फैसला 30 जून को कैबिनेट की बैठक के पहले होगा। नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर कई उलटफेर भी होंगे।

कांग्रेस के युवा नेता को पायलट की फटकार

कहते हैं पिछले दिनों अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस के एक युवा नेता को जबर्दस्त फटकार लगाई। ये युवा नेता कांग्रेस के एक संगठन के इंचार्ज बताए जाते हैं। इनके रिश्तेदार कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। चर्चा है कि युवा नेता के बारे में सचिन पायलट को कई तरह की शिकायतें मिली थीं। उन शिकायतों को लेकर सचिन ने युवा नेता की क्लास ले ली और जमीन में रहने की हिदायत भी दी। बताते हैं युवा नेता के पिछले एक साल में काफी पंख लग गए थे। वे कई वरिष्ठ लोगों को मात देकर तेजी से आगे बढ़ गए। तेज चाल के चलते उनके कदम फिसलने भी लगे थे, तो मौका लगते ही सचिन पायलट ने युवा नेता को धो दिया। कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में युवा नेता को सचिन पायलट की फटकार चर्चा का विषय है।

संतुलन साधने नीलू शर्मा को पर्यटन

कहते हैं संगठन में संतुलन साधने के मकसद से भाजपा हाईकमान ने राजनांदगांव के नेता नीलू शर्मा को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष की कुर्सी दे दी। कहा जाता है कि राजनांदगांव में राजनीति की धुरी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह के आगे-पीछे ही घूमती है। बताते हैं नीलू शर्मा राजनांदगांव से महापौर का चुनाव लड़ना चाहते थे। राजनांदगांव महापौर का पद सामान्य वर्ग के लिए था, लेकिन डॉ रमन सिंह की पसंद पर भाजपा ने मधुसूदन यादव को उम्मीदवार बना दिया। वे चुनाव जीत गए। मधुसूदन यादव ओबीसी हैं। सामान्य सीट पर ओबीसी को उम्मीदवार की भरपाई कहीं न कहीं करनी थी, सो नीलू शर्मा को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष की कुर्सी देकर कर दी गई। वैसे भाजपा की राजनीति में नीलू शर्मा को डॉ रमन सिंह की धारा का नहीं माना जाता है। नीलू शर्मा के पिता अशोक शर्मा का सुर डॉ रमन सिंह से नहीं मिलता था, पर मुख्यमंत्री रहते डॉ रमन सिंह ने संतुलन के लिए अशोक शर्मा को पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाया था।

भतपहरी के पीछे लगे ठेकेदार

कहते हैं लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता विजय कुमार भतपहरी के पीछे कुछ ठेकेदार लग गए हैं और उन्हें खो करने के चक्कर में हैं। विजय कुमार भतपहरी दोबारा ईएनसी बनकर आए हैं। वे पिछली कांग्रेस सरकार में भी ईएनसी थे और काफी साल चले भी। लेकिन बाद में सरकार उनसे नाराज हो गई और हटा दिया, उनकी जगह के के पीपरी को ईएनसी बना दिया। पीपरी के रिटायरमेंट के बाद भतपहरी को फिर मौका मिल गया। एक तो विभाग में भतपहरी के अलावा कोई सीनियर नहीं थे, विजय भतपहरी ने गणित फिट करने के अलावा केमेस्ट्री भी अपने अनुकूल कर लिया। चर्चा है कि लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ईएनसी के पद पर किसी और को बैठना चाहते थे, विजय भतपहरी ने ऊपर से पव्वा लगा लिया। अब देखते हैं ठेकेदारों की लॉबी विजय भतपहरी को हिला पाती है या नहीं।

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी जल्द

कहते हैं जल्द ही प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बनने वाली हैं। नई कार्यकारिणी के लिए प्रदेश इकाई केंद्रीय संगठन को सूची भेजेगी। केंद्रीय संगठन ही प्रदेश कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर लगाएगा। उम्मीद की जा रही है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी पांच-सात दिन में घोषित कर दी जाएगी। पार्टी संगठन ने नई कार्यकारिणी में जगह देने के लिए कुछ नेताओं से बायोडाटा भी मांगा है। बताते हैं पार्टी संगठन ने ऐसे लोगों से भी बायोडाटा की मांग की है, जो दशकों से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं और पहले भी संगठन और सत्ता में रह चुके हैं। बायोडाटा के लिए संगठन के एक पदाधिकारी के कार्यालय से नेताओं के पास संदेश गया है। चर्चा है कि बायोडाटा के संदेश से पार्टी के कुछ कद्दावर नेता भड़क गए हैं। वे कह रहे हैं पार्टी के लिए जीवन खपाने के बाद भी उन्हें अब पद के लिए बायोडाटा देना होगा।

कौन होगा जल संसाधन का ईएनसी

जल संसाधन विभाग के ईएनसी इंद्रजीत उइके 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। उइके की जगह जल संसाधन विभाग का अगला ईएनसी कौन होगा, इस पर गुणा-भाग शुरू हो गया है। कहते हैं जल संसाधन विभाग के ईएनसी पद के लिए बिलासपुर के चीफ इंजीनियर जे आर भगत और चीफ इंजीनियर बांगो दीपक बुमेरकर दावेदार हैं। इनमें भगत की सर्विस आठ माह और बुमेरकर की चार माह बची है। वरिष्ठता में दोनों बराबर माने जा रहे हैं, ऐसे में सरकार लंबे पीरियड वाले को प्राथमिकता देती है तो भगत का चांस ज्यादा लग रहा है। जल संसाधन विभाग के अफसरों को सरकार के फैसले का इंतजार है।

संघ की बैठक में साय सरकार के काम की समीक्षा होगी

खबर है कि आरएसएस के दिल्ली स्थित झंडेवालान दफ्तर में आगामी चार से छह जुलाई तक देशभर के प्रांत प्रचारकों की बैठक होने वाली है। इसमें छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक अभयराम भी शामिल होंगे। वैसे तो यह बैठक मूलतः संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के लिए हो रही है, पर बैठक में भाजपा शासित राज्यों के कामकाज पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ की साय सरकार के कामकाज पर विश्लेषण हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कामकाज के आब्जर्वेशन के लिए तीन-चार पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। पर्यवेक्षकों ने प्रांत प्रचारक को रिपोर्ट दे दी है। माना जा रहा है कि प्रांत प्रचारकों की बैठक में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पेश की जा सकती है और उस पर चर्चा भी हो सकती है।

दुश्मनों पर भारी पड़े मंत्री जी

कहते हैं राज्य के एक मंत्री को निपटाने में कुछ लोग लगे थे, उनके खिलाफ फर्जी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय को भ्रष्टाचार की शिकायत भेजी गई। मंत्री जी के दुश्मनों ने तो बड़े शातिर तरीके का खेल खेला था। शिकायत के एक बड़े नाम और बड़ी संस्था को हथियार बनाया था। जाँच पड़ताल में पता चला कि शिकायतकर्ता ने तो मंत्री जी के बारे कोई शिकायत ही नहीं की थी। नाम और संस्था के उपयोग को लेकर मामला पुलिस तक पहुंच गया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चर्चा है कि मंत्री जी की शिकायत के पीछे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का हाथ हो सकता है। जाँच में सब कुछ खुलासा होगा, पर अभी तो मंत्री जी ने दुश्मनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वार का प्रतिवार कर दिया है।

चपेटे में भूपेश बघेल के साथी

विजय भाटिया के बाद के के श्रीवास्तव को भी जाँच एजेंसियों ने दबोच लिया। दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करीबी माना जाता रहा है। भूपेश बघेल सत्ता में थे तब दोनों उनके काफी नजदीकी माने जाते थे। खबर है कि भूपेश बघेल कई बार के के श्रीवास्तव के बिलासपुर आवास गए भी। चर्चा है कि जाँच एजेंसियों ने विजय भाटिया और के के श्रीवास्तव को ऐसा उलझा दिया कि भूपेश बघेल चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस राज में सत्ता की चौकड़ी में शामिल कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद विजय भाटिया और के के श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प

अक्षय जल, सुरक्षित कल

जल गंगा संवर्धन अभियान

समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री

30 जून, 2025 । दोपहर 12 बजे
मंडी प्रांगण, खण्डवा, मध्यप्रदेश

'जल की हर बूंद में आने वाले कल का भविष्य छिपा है। इसलिए इस अमूल्य धरोहर की किसी भी मूल्य पर रक्षा करना हमारा दायित्व है।'

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

जल संरक्षण का 'जन संकल्प'

जल संचय में वृद्धि

- ₹2048 करोड़ लागत के 83 हजार से अधिक खेत तालाबों का निर्माण पूर्ण, जिससे खेत का पानी खेत में सिंचित होगा
- ₹254 करोड़ लागत से 1 लाख से अधिक कूप रीचार्ज
- अमृत सरोवर 2.0 के तहत ₹ 354 करोड़ लागत से 1 हजार से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण
- शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्त्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई एवं 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण पूर्ण

जनभागीदारी

- 40 लाख लोगों की भागीदारी से 5 हजार से अधिक जल स्त्रोतों का हुआ जीर्णोद्धार
- My Bharat पोर्टल के माध्यम से 2.30 लाख से अधिक जलदूत बनाए गए
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी चौपाल का आयोजन

तकनीकी नवाचार

- GIS आधारित SIPRI सॉफ्टवेयर के उपयोग से जल स्त्रोतों का चयन एवं AI आधारित मॉनिटरिंग की गई
- नर्मदा परिक्रमा पथ एवं अन्य तीर्थ मार्गों के डिजिटलीकरण के जरिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जा सकेगा ख्याल

पर्यावरणीय एवं कृषि प्रभाव

- 57 प्रमुख नदियों में मिलने वाले 194 से अधिक नालों का चिह्नांकन एवं उनके शोधन के लिए योजना तैयार
- जैव विविधता संरक्षण हेतु घड़ियाल और कछुओं का किया गया जलावतरण
- 145 नदियों के उद्गम क्षेत्रों को चिन्हित कर हरित विकास हेतु योजना तैयार
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना में 5600 हेक्टेयर में पौधरोपण प्रारंभ
- वन्य जीवों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 2500 से अधिक तालाब, स्टॉप डैम का निर्माण
- पौधरोपण हेतु लगभग 6 करोड़ पौधों की नर्सरी विकसित

वॉटरशेड हेतु कार्य

- ₹1200 करोड़ लागत की 91 वॉटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत, 5.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी सिंचाई सुविधा
- 9000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं के जरिए किसानों को 1 वर्ष में दो से तीन फसलों का मिल रहा लाभ

D-11056/25

सीधा प्रसारण Webcast.gov.in/mp/cmevents @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @JansamparkMP JansamparkMP

#जल_गंगा_संवर्धन_अभियान_MP